राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 237 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शनिवार,20 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने किसान प्रदर्शन से संबंधित टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने पांच दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद रवि को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन के समक्ष पेश किया, जहां से दिशा रवि को जेल भेजा गया। पुलिस ने कहा कि फिलहाल दिशा रवि की हिरासत की आवश्यकता नहीं है और मामले में सह-आरोपी शांतनु मुकुल और निकिता जैकब के जांच में शामिल होने के बाद दिशा रवि से आगे की पूछताछ की जरूरत हो सकती है।

स्वामी ने अपनी ही सरकार को घेरा

नई दिल्ली, (संवाददाता)। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी सड़क पर उतरने लगे हैं। इस बीच बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपनी ही मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस मुद्दे पर जनता की राय एक है, कि कीमतों में बढ़ोतरी शोषण करने वाला है। मोदी सरकार को पेट्रोल, डीजल से लेवी हटाना चाहिए।

नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेंगी ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली, नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं होंगी। यह परिषद सरकार के थिंक टैंक की शीर्ष संस्था है। सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य हैं। एक आधिकारिक वक्तव्य के मुताबिक, शनिवार को होने वाली परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे।

किसानों ने धोखा दिया: पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव पुलिस मुख्यालय में वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच अभी भी चल रही है। अभी तक की जांच के आधार पर मीडिया को अवगत कराते हुए पुलिस आयुक्त ने बताया कि गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा को हम खुफिया तौर पर विफलता नहीं मानते, क्योंकि पुलिस को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के संकेत जरूर मिले थे। लेकिन आपको बता दें कि किसानों ने इतना बड़ा धोखा देगा वह पता नहीं था। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली ने हिंसक रूप धारण कर लिया था। प्रदर्शनकारी दिल्ली के अंदर घुस गए थे और आईटीओ चौक और लाल किला में जमकर तोड़फोड़ किया और हुड़दंग मचाया।

अपने सालाना लेखा-जोखा में पुलिस आयुक्त ने यह भी बताया कि 5 वर्षा के मुकाबले 2020 में सबसे ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए गए। आगे उन्होंने कहा कि पिछले साल अलग-अलग संगठनों के 32 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आयुक्त ने इस दौरान राजधानी में सभी तरह के अपराधों का ब्योरा पेश किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि खालिस्तानी, करकर और पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ने बताया कि पाकिस्तान और दूसरे देशों में भारत के खिलाफ पनप रहे आतंकी साजिशों पर नजर रखा जा रहा है।

इस दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली दंगे और कोरोना काल दिल्ली पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन पुलिस ने अपने साहस और संयम का परिचय देते हुए सराहनीय काम किया।

कमिश्नर ने कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे से जुड़े 750 से ज्यादा मामलों की जांच के लिए तकनीक का व्यापक तरीके से इस्तेमाल करते हुए 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया।

दंगों के सिलसिले में 755 एफआईआर दर्ज की गईं और पुलिस बल ने पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की। पिछले साल 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।

उन्होंने कहा कि आपको पता है कि दंगे में 53 लोगों की मौत हुई और 581 लोग घायल हुए थे। पिछले साल 24 और 25 फरवरी को दंगों के दौरान सबसे ज्यादा हिंसक घटनाए हुईं। कुल 755 एफआईआर दर्ज की गईं और हमने सुनिश्चित किया कि किसी को यह शिकायत ना रहे कि उनके मामले को नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि मामलों की जांच के लिए तीन एसआईटी बनाई गईं।

श्रीवास्तव ने कहा कि एक मामला दंगों के पीछे की साजिश को उजागर करने के लिए दर्ज किया गया। इसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की, जबकि बाकी मामलों की जांच उत्तर-पूर्वी जिले की पुलिस ने की।

आतंक फैलाने वालों में शिक्षित लोग भी शामिल : प्रधानमंत्री

कोलकाता, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वभारती के छात्रों को संबोधित करते हुए रबींद्रनाथ टैगोर और शिवाजी पर लिखी उनकी कविता का जिक्र किया। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को गुरुदेव का विजन बताते हुए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने छात्रों को विजन डॉक्युमेंट बनाने को कहा कि भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने तक विश्वभारती के 25 लक्ष्य क्या होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कुछ ही समय के अंतराल में दूसरी बार आपको संबोधित करने का मौका मिला है। आप सभी युवा साथियों को, माता-पिता को और गुरुजनों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया में आतंक फैलाते हैं, डर फैलाते हैं। उनमें भी कई उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जो दुनिया महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। अस्पतालों में डटे रहते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ विचारधारा का प्रश्न नहीं है। मूल बात तो माइंड सेट है। आप क्या करते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि आपका माइंड सेट निगेटिव है या पॉजिटिव। आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या समाधान का। यह हमें तय करना होता है। अगर हम सिर्फ अपना हित देखेंगे, तो हम हमेशा चारों तरफ समस्या, मुसीबत, आक्रोश नजर आएगा। छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा अगर आप खुद से उठकर, स्वार्थ से उठकर नेशन फर्स्ट की अप्रोच लेकर आगे बढ़ेंगे तो यह समस्या में सॉल्यूशन ढूंढने का मन करेगा। बुरी स्थिति में भी अच्छा करने का मन करेगा। अगर आपकी नीयत साफ है और निष्ठा मां भारती के प्रति है तो आपका हर निर्णय, आपका हर आचरण किसी न किसी समस्या के समाधान की तरफ ही बढ़ेगा। विश्वभारती में पीएम मोदी ने कहा कि सफलता और असफलता हमरा वर्तमान भविष्य नहीं तय करती। जैसा सोचा वैसा परिणाम न मिले लेकिन फैसला लेने से डरना नहीं चाहिए। वह हमारे लिए सबसे संकट का समय है।

नया करने का रिस्क लेने का और आगे बढ़ने का जज्बा रहेगा तब तक मुझे देश के भविष्य को लेकर चिंता नहीं रहेगी। जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए मैं खुद भी आपके समर्थन में खड़ा हूं। पीएम मोदी ने छात्रों को विजन डॉक्युमेंट बनाने को कहा। पीएम मोदी ने कहा मेरा आग्रह है, अगले 25 वर्षों के लिए विश्व भारती के विद्यार्थी मिलकर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएं। वर्ष 2047 में, जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का समारोह बनाएगा, तब तक विश्व भारती के 25 सबसे बड़े लक्ष्य क्या होंगे, यह इस विजन डॉक्यूमेंट में रखा जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस वर्ष अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। विश्व भारती के प्रत्येक विद्यार्थी की तरफ से देश को सबसे बड़ा उपहार होगा कि भारत की छवि को और निखारने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें।

पीएम मोदी ने विश्वभारती के छात्रों से कहा जिस दिन फैसला लेने में डर लगने लगे, समझना उस दिन आपकी जवानी चली गई। पीएम मोदी ने बेटियों के योगदान का जिक्र कर कहा भारत की आत्मनिर्भरता, देश की बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं है।

भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी नेताजी की देशभक्ति और शहादत : शाह

कोलकाता, (एजेंसी)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भुला देने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन उनकी देशभक्ति और शहादत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। बंगाल के क्रांतिकारियों के सम्मान में यहां स्थित नेशनल लाइब्रेरी में आयोजित शौर्यांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बहुत प्रयास किए गए कि सुभाष बाबू को भुला दिया जाए, परन्तु कोई कितना भी प्रयास करे, उनका कर्तव्य, देशभक्ति और उनका सर्वोच्च बलिदान पीढ़ियों तक भारत वासियों के जहन में जस का तस रहने वाला है। उन्होंने कहा कि सुभाष बाबू को देश की जनता इतने वर्ष के बाद भी उतने ही प्यार और सम्मान से याद करती है, जितना उनके जीवित रहने और संघर्ष के दौरान करती थी। एक उत्कृष्ट छात्र के रूप में सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके आईसीएस की परीक्षा पास करने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता सेनानी ने नौकरी छोड़ दी और स्वाधीनता के आंदोलन में कूद गए, ताकि यह संदेश जाए कि अंग्रेजी हुकूमत के अधीन आरामदेह जीवन जीने के मुकाबले देश उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। शाह ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वह दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और एक बार तो उन्होंने महात्मा गांधी के उम्मीदवार को हराया। उन्होंने देश के युवाओं से आग्रह किया कि वह सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके संघर्षें के बारे में ठीक से पढ़ें और उनकी शिक्षा को आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि जो युवा पीढ़ी अपने इतिहास को जानती है, वही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। शाह ने इस अवसर पर खुदीराम बोस और रास बिहारी बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी बिप्लबी बांग्ला का भी उद्घाटन किया और एक साइकिल रैली को रवाना किया।

श्रीनगर के भगत बरजुल्ला में आतंकी हमला, दो पुलिसकर्मी शहीद; फुटेज में गोलियां बरसाता कैद हुआ आतंकी

श्रीनगर । कश्मीर घाटी में पिछले 16 घंटों के भीतर तीसरी आतंकी वारदात पेश आई है। आतंकवादी ने जिला श्रीनगर के भगत बरजुल्ला इलाके के मुख्य बाजार में खड़े दो पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाकर उन्हें शहीद कर दिया। हमले को अंजाम देने वाले आतंकी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें वह दुकान के बाहर खड़े एक पुलिसकर्मी पर गोलियां बरसा वापस भागते हुआ नजर आ रहा है।

वायरल हो रहे वीडियो में आतंकी ने फिरन पहन रखा है और उसी के भीतर उसने एके-47 छिपा रखी थी। बड़ी आसानी के साथ आतंकी मुख्य बाजार तक पहुंचता है और वहां एक दुकान के बाहर खड़े पुलिसकर्मी पर गोलियां बरसाकर वापस भाग जाता है। गोलीबारी की इस घटना के बाहर बाजार में हड़कंप मच गया। दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस हमले को अंजाम देते हुए आतंकी ने एक अन्य पुलिस कर्मी पर भी गोलियां बरसाई। आतंकी के फरार होने के बाद स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से दोनों पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उन्होंने इलाज के दौरान जख्मों का ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहीद सोहेल अहमद ने एसएमएचएस अस्पताल में दम तोड़ा जबकि दूसरे पुलिसकर्मी मोहम्मद युसूफ ने पुलिस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकी की तलाश शुरू कर दी है। द रजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि पिछले 16 घंटों के भीतर घाटी में यह तीसरी आतंकी वारदात पेश आई है। गत वीरवार शाम को सुरक्षाबलों और

आतंकियों के बीच शोपियां में मुठभेड़ शुरू हुई थी। शुक्रवार तड़के सुरक्षाबलों ने इलाके में छिपे लश्कर के तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया था। दूसरी घटना तड़के ढाई बजे के करीब जिला बडगाम में पेश आई। यहां भी तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद हो गया जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।

भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की 10वें दौर की वार्ता कल, पैंगोंग के बाद अन्य क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार को सुबह 10 बजे से भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की 10 वें दौर की वार्ता होगी। सैन्य सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। यह बातचीत मोल्डो बॉर्डर प्वाइंट पर आयोजित होगी, जो चीन के नियंत्रण में है। बताया गया है कि पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों से पीछे हटने के बाद दोनों पक्षों के बीच अन्य जगहों से भी पीछे हटने की प्रक्रिया पर बातचीत होगी, जहां गतिरोध की स्थिति बरकरार है। विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि सैन्य और राजनयिक स्तर पर निरंतर वार्ता के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सेना के बीच टकराव खत्म करने को लेकर सहमति बनी।

बता दें कि बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर समझौता हो गया है। इसके तहत दोनों पक्ष अग्रिम मोर्चे पर तैनात अपने सैनिकों को चरणबद्ध तरीके वापस हटाएंगे। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ वार्ता के दौरान भारत की रणनीति और दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर आधारित है। हम अपने क्षेत्र का एक इंच हिस्सा भी किसी को लेने नहीं देंगे। यह हमारे दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि हम एक समझौते की स्थिति में पहुंच गए हैं।

बता दें कि पैंगोंग इलाके में सैन्य टकराव खत्म करने के लिए हुए समझौते के अनुसार दोनों देशों के सैनिकों के अपने-अपने अग्रिम मोर्चे से पीछे लौटने और अप्रैल, 2020 के पहले की स्थिति सुनिश्चित करने पर सहमति बनी थी। पैंगोंग झील इलाके में सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर हुए समझौते के तहत चीनी सेना पैंगोंग झील के करीब फिंगर आठ से पूरब की ओर अपनी पुरानी जगह पर रहेगी। वहीं भारतीय सेना फिंगर-तीन के पास धान सिंह थापा पोस्ट के स्थायी बेस पर रहेगी। मई 2020 में चीनी सैनिकों द्वारा सीमा के उल्लंघन के बाद भारत ने अक्रामक रुख अपना लिया था और हजारों सैनिक तैनात कर दिए थे। इससे तनाव और गहरा गया था।

इससे पहले दोनों देशों के बीच मई 2020 से जारी तनाव के बीच 23 जनवरी को दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की वार्ता हुई थी। दोनों देशों ने इसे सकारात्मक बताया था।

अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर ठोका मानहानि का केस, अदालत ने जारी किया समन

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चल रही राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी विवाद में भी तब्दील होती दिख रही है। सूबे की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। इस केस की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि अमित शाह को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। वह अपने वकील के जरिए भी पक्ष रख सकते हैं।

अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने बताया, स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को व्यक्तिगत या फिर अपने वकील के जरिए 22 फरवरी को 10 बजे पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2018 में एक रैली के दौरान अमित शाह की ओर से अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए आरोपों का है। 11 अगस्त 2018 को बीजेपी की युवा स्वाभिमान रैली के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे पर करप्शन के आरोप लगाए थे।

अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर मानहानि केस में अमित शाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर छवि खराब की है। अमित शाह ने कहा था, ...नारदा, शारदा, रोज वैली, सिंडिकेट करप्शन, भतीजे का करप्शन। ममता बनर्जी ने लगातार भ्रष्टाचार किए। अमित शाह ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। इसके अलावा अमित शाह के एक और बयान का अभिषेक बनर्जी ने हवाला दिया है।इस बयान में अमित शाह ने कहा था, बंगाल के गांवों के लोगों क्या आपके गांव तक पैसा पहुंचता है? जोर से बताइए। क्या आपके गांव तक पैसा पहुंचता है? यह कहां चला जाता है? मोदी जी भेजते हैं। आखिर 3,59,000 करोड़ रुपया कहां चला गया? क्या यह भतीजे और सिंडिकेट को गिफ्ट कर दिया गया। या फिर तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।

पतंजलि आयुर्वेद ने लॉन्च की कोरोना की नई दवा

नई दिल्ली, (संवाददाता)। कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोरोनिल नाम से इम्युनिटी बूस्टर दवा लॉन्च कर चुकी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने अब एक नई दवा पेश की है। बाबा रामदेव का कहना है कि यह दवा डब्लूएच्ओ द्वारा सर्टिफाइड है। इस दवा का नाम भी कोरोनिल टैबलेट ही है। पतजंलि का कहना है कि इस दवा से दुनिया के 158 देशों को कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। इससे पहले पतंजलि की ओर से बीते साल जून में कोरोनिल नाम से दवा लॉन्च करने का दावा किया था। इस पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद पतंजलि ने कहा था कि यह दवा कोरोना को खत्म करने का दावा नहीं करती है बल्कि इम्युनिटी बूस्टर है। दवा की लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। दवा की लॉन्चिंग के साथ ही इस दौरान एक रिसर्च पेपर भी जारी किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉ. हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। पतंजलि आयुर्वेद की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस दवा को 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। पतंजलि का कहना है कि इन दवाओं से न सिर्फ इम्युनिटी मजबूत होगी बल्कि कोरोना को भी खत्म किया जा सकेगा। पतंजलि ने जो नई दवाएं लॉन्च की हैं, उनमें कोरोनिल और श्वासारी के अलावा पीड़ानिल, आर्थोग्रिट, मधुनाशिनी व मधुग्रिट, मुक्तावटी, थायरोग्रिट, प्रोस्टोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, सिस्टोग्रिट आदि प्रमुख हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर पतंजलि के रिसर्च पेपर का विमोचन करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि पतंजलि और केंद्र सरकार का एक ही सपना है कि नई तकनीक के आधार पर आयुर्वेद को स्थापित किया जा सके। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि यदि कोरोना के दौर में आयुर्वेदिक दवाओं को पहचान मिलती है तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। कोरोना के दौर में आयुर्वेद की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 50 फीसदी तक पहुंच गई है, जो कोरोना से पहले 15 से 20 फीसदी के करीब ही रहा करता था। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि ने दवा सिर्फ कारोबार के लिए नहीं बनाई है बल्कि हमने उपचार और उपकार के लिए कोरोना की दवाओं को तैयार किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगले 30 सालों तक इस तरह से आयुर्वेद पर काम करें कि डब्लूएच्ओ का हेड ऑफिस ही भारत में आ जाए।

नाइजीरिया में बड़ी घटना: सेना की वर्दी में आए हमलावरों ने कॉलेज को निशाना बनाया; एक स्टूडेंट की मौत, सैकड़ों छात्र और शिक्षक बंधक

नाइजीरिया। नाइजीरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक साइंस कॉलेज को सेना की वर्दी पहनकर आए हमलावरों ने निशाना बनाया है। गोलीबारी में एक छात्र की मौत हो गई है। बदमाशों ने 100 से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों को बंधक बनाया

है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हमलावर कौन हैं। मौके पर नाइजीरिया पुलिस और सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं।

हमले के दौरान एक हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स थे

नाइजीरियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त कॉलेज में एक हजार से ज्यादा छात्र मौजूद थे। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बड़ी संख्या में छात्रों और कॉलेज स्टाफ को बाहर निकाल लिया। हालांकि अभी भी 100 से ज्यादा छात्र और शिक्षक बंधक हैं। जिस कॉलेज में ये हमला हुआ है वो सरकारी है।

कुछ दिन पहले भी हुआ था हमला

नाइजीरिया में ये पहली बार नहीं है जब बदमाशों ने स्कूल को निशाना बनाया है। कुछ दिन पहले भी यहां बदमाशों ने एक स्कूल में सैकड़ों छात्रों को बंधक बना लिया था। बाद में नाइजीरियन सरकार से समझौता करने के बाद छात्रों को छोड़ दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां पैसों के लिए बदमाश आएदिन किडनैपिंग, मर्डर, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।

संदिग्ध आतंकी की नागरिकता का मामला: न्यूजीलैंड की पीएम ने कहा- ऑस्ट्रेलिया की सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, हम उनसे परेशान हो चुके

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने की आरोपी महिला के मामले में उपजे विवाद के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया पर निशाना साधा है। उन्होंने

ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाया है। अर्डर्न ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से एक के बाद एक खड़ी की जा रही परेशानियों को झेलते-झेलते न्यूजीलैंड थक चुका है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 26 साल की महिला ने ऑस्ट्रेलिया और

अपने दो बच्चों के साथ सीरिया से तुर्की में प्रवेश करने के दौरान उसे पकड़ लिया गया था। इसके बाद से वह न्यूजीलैंड में निर्वासन का सामना कर रही है। हालांकि अर्डर्न ने कहा कि महिला को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना चाहिए।

न्यूजीलैंड दोनों की नागरिकता तब तक कायम रखी थी, जब तक कि कैनबरा ने पिछले साल इसे रद्द नहीं कर दिया था। अपने दो बच्चों के साथ सीरिया से तुर्की में प्रवेश करने के दौरान उसे पकड़ लिया गया था। इसके बाद से वह न्यूजीलैंड में निर्वासन का सामना कर रही है। हालांकि अर्डर्न ने कहा कि महिला को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना चाहिए।

तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने पहचाना

अर्डर्न ने कहा कि महिला को तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने ढूस के सदस्य के रूप में पहचाना है, वह बचपन से ही न्यूजीलैंड में नहीं रहती थी। जब वह 6 साल की थी, तब उसके परिवार ने न्यूजीलैंड छोड़ दिया था। इसके बाद वे ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और वहां की नागरिकता हासिल कर ली थी। इसके बाद वे ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर ही सीरिया गए।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया

इस बीच, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उनका काम ऑस्ट्रेलिया के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि संसद में पारित कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त आरोपी की दोहरी नागरिकता को स्वतः ही रद्द कर देता है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री से बात करेंगे।

टेंशन में प्रिंस सलमान : बाइडेन ने अब तक सऊदी प्रिंस से बातचीत नहीं की

व्हाइट हाउस ने कहा- सही वक्त का इंतजार कीजिए

वाशिंगटन। जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लिए करीबन एक महीना पूरा होने को है। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की। दुनियाभर की नजरें इस बात पर हैं कि वे अमेरिका के दो सबसे बड़े सहयोगियों इजराइल और सऊदी अरब के शासन प्रमुखों से कब बात करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बाइडेन ने बुधवार रात बातचीत कर ली। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को अब भी व्हाइट हाउस से फोन का इंतजार है।

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कई दशकों के सबसे अहम सहयोगी और अमीर देश के शासक प्रिंस सलमान को बाइडेन आखिर क्यों इंतजार करा रहे हैं। सऊदी को लेकर व्हाइट हाउस के हालिया बयान भी उम्मीद जगाने वाले नहीं रहे।

व्हाइट हाउस का रूखा बयान

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की से सऊदी किंग और बाइडेन की संभावित बातचीत पर सवाल हुआ।

उन्होंने कहा- हमने पहले ही साफ कर दिया है कि सऊदी से रिश्तों को लेकर हम कई चीजों पर विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। प्रेसिडेंट बाइडेन सऊदी प्रिंस से कब बात करेंगे, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।

दो मुद्दों पर बाइडेन सख्त रहेंगे

अक्टूबर 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की तुर्की में सऊदी काउंसलेट में हत्या हुई थी। माना जाता है कि रॉयल फैमिली की आलोचना करने पर उन्हें मारा गया। बाइडेन जब विपक्ष में थे तो उन्होंने सऊदी सरकार पर सीधा निशाना साधा था। अब वे राष्ट्रपति हैं और प्रिंस सलमान जानते हैं कि बाइडेन दोषियों को सजा दिलाने के लिए उन पर दबाव डालेंगे। दूसरा मुद्दा यमन के हूती विद्रोहियों का है। अरब देश इन पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका इनके पक्ष में खड़ा हो गया है।

ट्रम्प से अलग नीति है बाइडेन की: एक रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रम्प के दौर में प्रिंस सलमान को खूब तवज्जो मिली। खशोगी की हत्या का मुद्दा भी नहीं उठा, लेकिन बाइडेन इन सब चीजों को सहन नहीं करेंगे। ये वे पहले ही साफ कर चुके हैं। ट्रम्प के दामाद और मिडल-ईस्ट के लिए उनके स्पेशल एडवाइजर जेराड कुश्नर और प्रिंस के बीच दोस्ताना रिश्ते रहे। ट्रम्प का फोकस अरब देशों और इजराइल के बीच दोस्ताना रिश्ते बनाना था। वे इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे। इजराइली सूत्रों ने साफ कर दिया था कि प्रिंस सलमान और नेतन्याहू के बीच सऊदी अरब में एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी।

सलमान के सामने नए चैलेंज होंगे: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रूड ने पिछले दिनों एक आर्टिकल में लिखा- बाइडेन जल्द डेमोक्रेसी समिट करेंगे।

इसमें चीन में उईगर मुस्लिमों और दूसरे मानवाधिकारों पर चर्चा होगी। इसमें सऊदी अरब का मुद्दा भी उठेगा। तब प्रिंस सलमान के सामने नए चैलेंज आ सकते हैं। हालांकि, बाइडेन सऊदी पर उतने सख्त नहीं हो सकते, जितने चीन पर। अमेरिका कभी सऊदी अरब को खुद से दूर नहीं होने देगा। दोनों देशों के साझा हित हैं। हां, सऊदी को बाइडेन की कुछ शर्तें जरूर माननी होंगी। दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद दिख सकते हैं, लेकिन ये दूर कर लिए जाएंगे।

इमरान को झटका: श्रीलंका दौरे पर वहां की संसद में भाषण नहीं दे सकेंगे इमरान; राजपक्षे सरकार को कश्मीर मुद्दा उठाने की आशंका थी

कोलंबो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 22 फरवरी को दो दिन के श्रीलंका दौरे पर जा रहे हैं। पहले उनके शेड्यूल में वहां की संसद में भाषण देना भी शामिल था, लेकिन ऐन वक्त पर श्रीलंकाई सरकार ने संसद के संबोधन का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोटबाया राजपक्षे सरकार को आशंका है कि इमरान भाषण के दौरान कश्मीर जैसा संवेदनशील मसला उठा सकते हैं और इससे भारत-श्रीलंका के संबंधों में तनाव आ सकता है।

श्रीलंका और भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। महामारी के दौर में भारत ने पहले तो दवाएं इस पड़ोसी देश को भेजी थीं और बाद में 5 लाख वैक्सीन डोज भी भेजे। ऐसे में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की सरकार भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहती।

पांच दिन पहले अहम फैसला: प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान पहली बार श्रीलंका यात्रा पर जा रहे हैं। यहां वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। पुराने शेड्यूल के मुताबिक,

इमरान श्रीलंकाई संसद में भाषण देने वाले थे। अब इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीलंकाई सरकार को आशंका है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भाषण में कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे का जिक्र कर सकते थे और इससे विवाद खड़ा हो सकता था। इसलिए, इमरान के संसद में भाषण के कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया गया है।

महामारी का बहाना

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि श्रीलंकाई सरकार ने कोविड-19 के मसले की ओट में इमरान के भाषण का कार्यक्रम रद्द किया है। श्रीलंकाई सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सरकार और विपक्षी पार्टियों ने इमरान के संसद में भाषण को लेकर लंबी चर्चा की। इस दौरान लगा कि इमरान कश्मीर का जिक्र कर सकते हैं और इससे भारत के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं।

SAARC समिट में भी उठाया था कश्मीर मुद्दा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके मंत्री लगभग हर इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं। पिछले साल भारत ने SAARC देशों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग का एजेंडा कोरोनावायरस से पैदा हुए हालात और इससे निपटने के लिए आपसी सहयोग था, लेकिन इसमें भी इमरान के मंत्री ने कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। श्रीलंकाई संसद को संबोधित करने वाले आखिरी नेता राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। 2015 में उन्होंने इस पड़ोसी देश की संसद को संबोधित किया था। श्रीलंकाई सरकार ने पिछले दिनों ट्रेड यूनियन्स और विपक्ष के दबाव में एक पोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था। यह प्रोजेक्ट भारत, जापान और श्रीलंका मिलकर पूरा करने वाले थे।

फ्रांस में कट्टरवाद के खिलाफ कानून: मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ेगी, जबरन और एक से ज्यादा शादियों पर भी सख्ती

वाशिंगटन। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन का प्रचार अब अमेरिका तक पहुंच गया है। वहां के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में किसानों के समर्थन में पूरे पन्ने का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ। इस विज्ञापन में लिखा है कि इस आंदोलन को 70 से ज्यादा मानवाधिकार संगठन समर्थन दे रहे हैं।

विज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने आंसू गैस, पानी, गिरफ्तारी कर दमन किया और कथित प्रायोजित हिंसा से शांतिपूर्ण विरोध का जवाब दिया। विज्ञापनदाताओं ने मांग की है कि मानवाधिकारों का हनन बंद हो। बता दें कि आंदोलन के पक्ष में हॉलीवुड गायिका रिहाना, पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने आवाज उठाई। उसके बाद भारत में टूलकिट मामला सामने आया, जिसमें 3 लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। टूलकिट मामले में राजद्रोह का सामना कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता शांतनु मुलुक के पिता ने बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र के बीड में मुलुक के पिता शिवलाल ने कहा, 'खुद को दिल्ली पुलिस के जवान बताने वाले दो लोग घर आए थे। उन्होंने बगैर वारंट के तलाशी ली और कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क और अन्य सामग्री जब्त कर लीं।' इसकी शिकायत पुलिस से की है।

कमल हासन बोले- देशद्रोह के नाम पर असंतोष दबा रहे

अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने सोशल मीडिया पर लिखा- शर्म की बात है कि असंतोष की आवाज औपनिवेशिक काल की तरह दबाई जा रही है। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया जाना चौंकाने वाला है।

बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल: ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनिका ने 6 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल शुरू किए

300 वॉलेंटियर हिस्सा लेंगे

लंदन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ने बच्चों के लिए स्पेशल कोविड-19 वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लंदन में इसके ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। कुल 300 बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनकी उम्र 6 से 17 साल के बीच है। इस ट्रायल का एक मकसद यह जानना भी है कि वर्तमान वैक्सीन इस उम्र वर्ग के बच्चों पर कितनी असरकारक है। फिलहाल, ब्रिटेन में वैक्सीन जिन लोगों को लगाई जा रही है, उनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है।

कई सेंटर्स पर ट्रायल

एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनिका का यह वैक्सीन ट्रायल शनिवार को शुरू हुआ। इसके लिए कंपनी ने कई सेंटर्स पर प्रॉसेस शुरू किया है। शुरुआत में 240 बच्चों को वैक्सीन डोज दिए गए हैं। 16 साल की मायरा ने सोशल मीडिया पर लिखा- मैं भी ट्रायल में बतौर वॉलेंटियर हिस्सा ले रहू हूं। उम्मीद है हमारे पास बेहतर नतीजे आएंगे। पूरी महामारी के दौरान मैं इस बात का इंतजार कर रही थी कि किस तरह योगदान दे सकती हूं।

दूसरा डोज चार हफ्ते बाद: ब्रिटेन में कुल तीन वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इनमें ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनिका के अलावा फाइजर-बायोएनटेक और मॉडर्ना शामिल हैं। कुछ बच्चों को पहला डोज दिया जा चुका है। दूसरा डोज चार हफ्ते बाद दिया जाएगा। क्लीनिकल ट्रायल्स कर रही टीम में शामिल नर्स हन्ना रॉबिन्सन ने कहा- हम ये देखना चाहते हैं कि वैक्सीन का इस उम्र के बच्चों पर भी वही असर

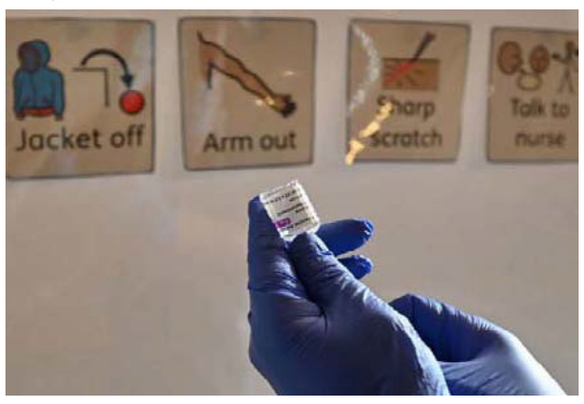

होता है जो वयस्कों पर हुआ है। इसकी एफिकेसी जानना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो बच्चों को भी महामारी से बचाया जा सकेगा और साल के आखिर तक इनके लिए भी वैक्सीन मौजूद हो सकता है।

विदेश से आने वालों के लिए नए नियम: कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट पोर्टल पर सबमिट करनी होगी, 72 घंटे से पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं

वाशिंगटन। दुनियाभर में सार्स कोविड-2 का म्यूटेंट वैरिएंट फैलने की स्थिति को देखते हुए सरकार ने विदेशों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये 2 अगस्त 2020 को जारी पुरानी गाइडलाइंस की जगह लेंगी और 22 फरवरी की रात 11.59 बजे से लागू हो जाएंगी। उड्डयन मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

यात्रा की तैयारी से पहले

यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा।

कोविड की निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।

सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट की ऑथेन्टिसिटी का डिक्लेरेशन भी देना होगा। यह झूठा पाया जाने पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। पैसेंजर्स को अपनी एयरलाइन के जरिए एयर सुविधा पोर्टल या उड्डयन मंत्रालय यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि जरूरत पड़ने पर वे 14 दिन होम क्वारैंटाइन या सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग के फैसले को मानेंगे। बिना निगेटिव रिपोर्ट के भारत आने की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो परिवार में किसी की मौत होने की वजह से यहां आ रहे हों। यह छूट लेने के लिए पैसेंजर्स को बोर्डिंग के कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। इस पर आखिरी फैसला सरकार लेगी।

बोर्डिंग से पहले

एयरलाइन सिर्फ उन्हीं यात्रियों को बोर्डिंग की इजाजत देगी जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन और निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट सबमिट की होगी। सभी यात्रियों को मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी। सभी यात्रियों को यात्रा से पहले कोरोना निगेटिव होने का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एयर सुविधा पोर्टल पर सबमिट करना होगा। इसके साथ ही 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री भी बतानी होगी।

सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से जुड़ी सभी जानकारियां देने के साथ ही यह सेलेक्ट करना होगा कि वे जहां फ्लाइट जा रही है वहीं उतरेंगे या फिर वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ेंगे। अगर वे दूसरे फ्लाइट पकड़ने का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उनके डिक्लेरेशन फॉर्म की कॉपी पर बड़े फॉन्ट में ञ्ज लिखा होगा।

च, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले वे पैसेंजर्स जो कनेक्टिंग फ्लाइट लेंगे, उन्हें टिकट बुकिंग के वक्त एयरलाइंस की तरफ से बताया जाएगा कि ट्रांजिट टाइम कम से कम 6-8 घंटे का रहेगा।

कोरोना दुनिया में: यूएन ने कहा- 130 देशों के पास वैक्सीन का एक सिंगल डोज तक नहीं, यह बहुत बड़ी नाइंसाफी

वॉशिंगटन। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.04 करोड़ से ज्यादा हो गया। 8 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 24 लाख 39 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

UN चीफ का दर्द

संयुक्त राष्ट्र महासचिव) एंतोनियो गुटेरेस के मुताबिक दुनिया में 130 देश हैं, जिनके पास कोविड-19 वैक्सीन का एक सिंगल डोज तक नहीं पहुंचा। यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान गुटेरेस ने कहा- बहुत दुख और गुस्सा है कि हम दुनिया के 130 देशों को महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन का एक डोज तक नहीं दे सके। वहीं, 10 देश ऐसे हैं जहां 75त्न वैक्सीनेशन प्रॉसेस पूरा हो चुका है। इससे साफ हो जाता है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना गैरबराबरी वाला है। अगर हमें महामारी से उबरना है तो किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर सबको वैक्सीन मुहैया करानी होगी।

इंग्लैंड के लिए नई परेशानी

इंग्लैंड में संक्रमण पर दो तिहाई तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन यहां एक नई परेशानी सामने आ रही है। 'द गार्डियन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड में अब संक्रमण की चपेट में युवा ज्यादा आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें बच्चे भी शामिल हैं। हाल ही में इम्पीरियल कॉलेज ने एक स्टडी की। इसमें साफ हुआ प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी संक्रमण के शिकार बन रहे हैं। देश में नए वैरिएंट्स सामने आए हैं,

लेकिन यह बहुत ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हुए। ज्यादातर मामले अब भी पुराने वैरिएंट के ही सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ होटल्स का वेंटिलेशन सिस्टम खराब है और इनकी वजह से संक्रमण खतरनाक रूप ले सकता है।

होटल्स का वेंटिलेशन सिस्टम खतरा

ब्रिटेन के कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के कुछ होटल्स का वेंटिलेशन सिस्टम खराब है और इनकी वजह से संक्रमण खतरनाक रूप ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक- दूसरे देशों से आने वाले कुछ लोगों को होटल्स में क्वारैंटीन किया जा रहा है। इन होटल्स का वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। इसकी वजह से एयरफ्लो के जरिए वायरस बाहरी हिस्सों में पहुंच सकता है और इसकी वजह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बना हुआ है। यह रिपोर्ट सरकार को भी सौंपी गई है।

अमेरिका एयरलाइंस को नुकसान

'द गार्डियन' ने अमेरिकी एविएशन एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि देश के सिविल एविएशन सेक्टर में 1984 के बाद पिछले साल यानी 2020 में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान 60फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। 2020 में सिर्फ 368 मिलियन पैसेंजर्स ने एयरलाइंस का इस्तेमाल किया। 2019 में यही संख्या 922.6 मिलियन थी। इसके पहले 1984 में यह आंकड़ा महज 351.6 मिलियन था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2023 या 2024 तक ही हालात सामान्य हो पाएंगे।

राकेश टिकैत को जल्द लगने वाला बड़ा झटका, गाजीपुर बॉर्डर से आ सकती है बुरी खबर

नई दिल्ली। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद करने की मांग पर अड़े किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन 86वें दिन में प्रवेश कर गया। दिल्ली-एनसीआर के चारों बॉर्डर (शाहजहांपुर, सिंघु, टीकरी और गाजीपुर) पर किसान बड़ी संख्या में जमा हैं और तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं, दिल्ली से सटे सिंघु और टीकरी बॉर्डर पर जहां युवा धरना-प्रदर्शन से दूरी बनाने लगे हैं तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी हालात कुछ ठीक नहीं हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अगुवाई में गाजीपुर बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। बृहस्पतिवार को एक तरफ प्रदर्शनकारियों ने रेल रोकने की घोषणा कर रखी थी और दूसरी तरह यूपी गेट धरनास्थल पर प्रदर्शनकारी और कम हो गए। मंच के सामने ही कुछ प्रदर्शनकारी बैठे रहे, जबकि उनके अधिकांश पंडाल खाली दिखाई दिए। शाम होते-होते प्रदर्शनकारियों की संख्या और कम हो गई। वहीं शाम को ईंधन के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर साथ लेकर पैदल मार्च किया और धरनास्थल पर विरोध जताया। 28 नवंबर को जब प्रदर्शनकारी कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर धरने पर बैठे थे तो उनकी संख्या ठीक-ठाक थी। पिछले महीने गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च के नाम पर दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार घट रही है। धरनास्थल पर लगाए गए पंडाल खाली हो गए हैं और मंच के सामने भी भीड़ कम होने लगी है। बृहस्पतिवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल रोको आंदोलन की घोषणा की गई थी। बावजूद इसके किसान लगातार प्रदर्शनस्थल छोड़कर जा रहे हैं।

निगम की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा को झटका, पार्षद रेखा दीक्षित ने थामा आप का दामन

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की पांच सीटों उपचुनाव के तहत आगामी 28 फरवरी को मतदान होना है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी भी जोरशोर से प्रचार में जुटी हुई है। वहीं, नेताओं को दलबदल करना जारी है। इस बीच शाहदरा जिले के पूर्व महामंत्री श्रवण दीक्षित और उनकी पत्नी रेखा दीक्षित ने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। रेखा दीक्षित अनारकली वार्ड से भाजपा की मौजूदा पार्षद हैं। आप के निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक और कृष्णानगर के विधायक एसके बग्गा ने टोपी और पटका पहना कर दोनों को सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर दुर्गेश पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने छह साल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाया है। बिजली, पानी, सड़क और वाई-फाई

सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। इन कार्यों से प्रभावित होकर लगातार दूसरे दलों के नेता आप से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में श्रवण दीक्षित और रेखा दीक्षित भी आप में शामिल हुए हैं।

की बेहतर सुविधा जनता को दी जा रही है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। इन कार्यों से प्रभावित होकर लगातार दूसरे दलों के नेता आप से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में श्रवण दीक्षित और रेखा दीक्षित भी आप में शामिल हुए हैं। चांदनी चौक के विधायक एसके बग्गा ने कहा कि श्रवण दीक्षित अपने क्षेत्र का बड़ा नाम हैं और उनकी पत्नी रेखा दीक्षित मौजूदा पार्षद हैं। अब दोनों आप परिवार का हिस्सा हो गए हैं। आशा है कि आने वाले समय में इनके बाकी साथी भी आप में शामिल हो जाएंगे। उधर, सदस्यता ग्रहण करने के बाद श्रवण दीक्षित ने कहा कि अब किसानों को सड़क पर सोना पड़ रहा है। किसान परिवार से होने के नाते उन्हें दुखी देखकर मेरा भाजपा में दम घुटता था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सभी कामों से प्रभावित होकर आप में शामिल होने का निर्णय लिया। उनके साथ अनारकली वार्ड से भाजपा संगठन मंत्री शिवकुमार वर्मा, बूथ संयोजक पुनीत अरोड़ा, भाजपा नेता विजय साई, योगेश गौड़, अजमल खान और रवि भारद्वाज ने आप की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर आप नेता जुगल अरोड़ा भी मौजूद रहे।

दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द बनेंगे घर मालिक

नई दिल्ली। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले दिल्ली के लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। तकरीबन 2000 अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब उनके घर जाकर मालिक बनाएगा, इससे लोगों की परेशानी कम होगी।

डीडीए की टीम इन कॉलोनियों के लोगों को न सिर्फ पीएम उदय योजना के बारे में जागरूक करेगी, बल्कि मालिकाना हक हासिल करने में भी मदद करेंगी। इस कार्य के लिए 80 पीएम उदय सहायक नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए डीडीए ने 16 दिसंबर, 2019 से अभियान शुरू किया था। करीब 13 माह में इस अभियान के तहत डीडीए के पास 12 फरवरी, 2021 तक तीन लाख 85 हजार 684 लोगों ने पंजीकरण कराया है और लगभग 55 हजार लोगों ने अपने दस्तावेज भी जमा करा दिए हैं, लेकिन मालिकाना हक अभी तक 4,271 लोगों को ही मिला है। इसका एक प्रमुख कारण लॉकडाउन भी रहा है।

अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो डीडीए ने इस योजना की रफ्तार देने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम उदय योजना को रफ्तार देने और मालिकाना हक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डीडीए की टीमें कॉलोनियों में जाकर पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने में मदद करेंगी। इसके अलावा संपत्ति का सर्वेक्षण भी करेंगी। जरूरत के मुताबिक इन कॉलोनियों में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। संपत्ति के दस्तावेज अपलोड करने के लिए पहले दो केंद्र बनाए थे। डीडीए ने अब इसके लिए 10 केंद्र बना दिए हैं। इनके अलावा 1,375 सामान्य सेवा केंद्र हैं, जिनके माध्यम से लोग मालिकाना हक प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। जीआइएस कंपनियों को भी सर्वेक्षण के साथ-साथ आवेदन कराने की अनुमति दे दी गई है।

दुनिया के पांच सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली भी

नई दिल्ली। गत वर्ष कोरोना संक्रमण की महामारी के कारण दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद वायु प्रदूषण का खतरा बरकरार रहा। दिल्ली विश्व के सर्वाधिक पांच प्रदूषित शहरों में शामिल रही, जहां वायु प्रदूषण के कारण वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा मौतें हुईं। अगर पांचों शहरों की बात करें तो मौत का आंकड़ा 1.60 लाख के पार हो जाता है। 85 अरब डॉलर यानी करीब 6167 अरब रुपये का आर्थिक नुकसान भी हुआ। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन ग्रीनपीस साउथ ईस्ट एशिया व वायु गुणवत्ता तकनीक कंपनी आइक्यूएयर ने 28 महानगरों की वायु गुणवत्ता का विश्लेषण किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, वायु प्रदूषण वैश्विक स्तर पर लोगों की सेहत के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक खतरा बन चुका है। खराब हवा के

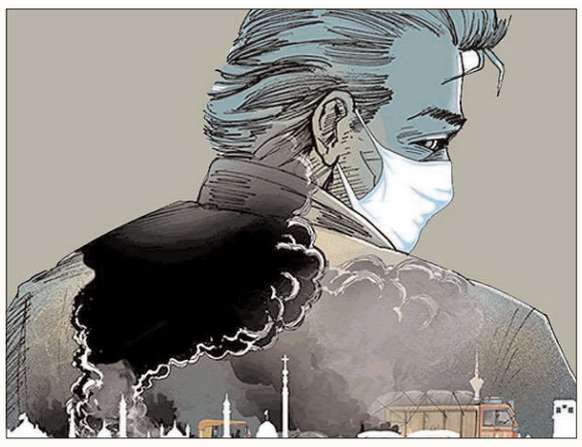

कारण हर साल 70 लाख लोग असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं। 10 में से नौ लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। इसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर व दिल संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले एशियाई शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या ज्यादा विकराल है। इसकी प्रमुख वजहें वाहनों से निकलने वाला धुआं, कोयला संचालित विद्युत उत्पादन इकाइयां, निर्माण, आतिशबाजी, वनों की कटाई, फसलों को जलाना और दावानल हैं। गत वर्ष दुनिया के पांच बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों की बात करें तो दिल्ली शीर्ष पर रही। यहां कुल 54 हजार मौतें हुईं और 8.1 अरब डॉलर यानी करीब 588 अरब रुपये का नुकसान हुआ। यह दिल्ली के 13 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बराबर है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ की तरफ से तय मानक से करीब छह गुना ज्यादा रहा। जापान की राजधानी टोक्यो में 40 हजार मौतें हुईं और उसे सबसे ज्यादा 43 अरब डॉलर यानी 3,122 अरब रुपये का नुकसान हुआ। दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 के कारण 10 लाख में से करीब 1,800 लोगों की मौत हो जाती है। बेहद छोटे प्रदूषक तत्व जिनका व्यास 2.5 माइक्रो मीटर से भी कम होता है, उन्हें पीएम 2.5 कहा जाता है। ये दुनियाभर में प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह माने जाते हैं। वर्ष 2015 में इसके कारण 42 लाख लोगों की मौत हुई थी। ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर की ग्रीनपीस शोध प्रयोगशाला के वायु प्रदूषण विज्ञानी एडन फैरो के अनुसार, प्रदूषण से न सिर्फ जान का नुकसान होता है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। समस्या बड़ी है और इसे खत्म करने के लिए बड़े प्रयासों की जरूरत है। ग्रीनपीस इंडिया के क्लाइमेट कैंपेनर अविनाश चंचल के अनुसार, 'हमें ऊर्जा के स्वच्छ स्नेतों पर ध्यान देना होगा। पैदल, साइकिल या सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। आइक्यूएयर के सीईओ फ्रैंक हैम्स कहते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में सरकार व संस्थाओं के साथ-साथ लोगों को निजी स्तर पर भी काम करना चाहिए।

जीवनभर की पूंजी रामकाज के लिए की अर्पित

नई दिल्ली। निधि समर्पण अभियान में एक से एक बढ़कर भावुक करने वाले क्षण आ रहे हैं। नजफगढ़ के नांगली में रहने वाले बुजुर्ग ओम प्रकाश सैनी ने अपने जीवनभर का जमा धन अर्पण कर दिया। वह वर्ष 2003 में स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए। शादी के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ तो एक बेटी गोद ली। पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी की। इस बीच पत्नी का निधन हो गया और मकान भी बिक गया। किसी प्रकार किराये पर एक कमरे में जीवन यापन कर रहे हैं। पेंशन ही सहारा है। उनके बैंक खाते में एक लाख रुपये शेष थे। स्वदेशी जागरण मंच की टोली जब उनके यहां पहुंची तो उन्होंने एक लाख 11 हजार 111 रुपये देने की पेशकश की। टोली ने दो दिन उन्हें विचार के लिए दिए। ओम प्रकाश सैनी डिगे नहीं, बल्कि 11 हजार रुपये दोस्तों व परिचितों से जुटाते हुए राशि अर्पित की।

दिल्ली में दहेज की मांग पूरी न होने पर पहली पत्नी के बाद अब दूसरी को भी दिया तलाक

नई दिल्ली। सीमापुरी इलाके में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद चुन्नी से पत्नी का गला घोंटने की कोशिश की। पीड़िता की बहन के विरोध करने पर आरोपित अपने परिवार को लेकर फरार हो गया। पीड़िता हीना ने थाने पहुंचकर तीन तलाक का मुकदमा दर्ज करवाया। कुछ ही देर में पुलिस ने आरोपित पति इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी नोएडा सेक्टर-11 में रहने वाले इरशाद नाम के व्यक्ति से 11 नवंबर 2020 को हुई थी।

यह इरशाद की दूसरी शादी थी। पहली पत्नी को भी उसने तलाक दिया था। शादी के कुछ वक्त बाद ही इरशाद ने दूसरी पत्नी को भी दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। पीड़िता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे पीटा जाता था। पति उसे ताने देता कि पहली शादी में उसे बीएमडब्ल्यू कार मिली थी, जबकि उसके पिता ने उसे कम कीमत वाली कार पकड़ा दी।

पति की प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता 17 जनवरी को पति का घर छोड़कर दिलशाद कालोनी स्थित अपने मायके आ गई। 17 फरवरी को दोपहर में उसका पति अपने माता-पिता को लेकर पीड़िता के घर पहुंचा। घर वालों ने हीना और उसके पति को बातचीत करने को कमरे में भेज दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने उसके साथ गाली-गलौज की। इसके बाद कहा उसकी मां ने उससे कहा है कि बेटे तेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। दो क्या तीसरी शादी भी करवा दूंगी। इसके बाद तीन बार तलाक बोल दिया। विरोध पर आरोपित चुन्नी से उसका गला घोंटने लगा, आवाज सुनकर जब पीड़िता की बहन कमरे में पहुंची तो आरोपित फरार हो गया।

चांदनी चौक में रात में मंदिर निर्माण, दिल्ली पुलिस के पूछने पर महंत बोले- जनता ने बनाया

नई दिल्ली। चांदनी चौक में हटाए गए 50 साल पुराने मंदिर के स्थान पर स्थानीय लोगों ने रातभर में फिर हनुमान बना दिया। इस मंदिर के बनाए जाने का पता शुक्रवार को चला। मंदिर में हनुमान जी की वही मूर्ति रखी गई है जो पहले वाले मंदिर में थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टोर से बृहस्पतिवार रात को ही मूर्ति को लाया गया। इसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया। सूत्र बताते हैं कि एक दिन पहले मंदिर को स्थापित किया जाना था, लेकिन किन्ही कारणों से उस दिन यह सिरे नहीं चढ़ पाया। वहीं, स्थानीय लोगों ने मिलकर बृहस्पतिवार रातभर में स्टील और लोहे से दूसरा हनुमान मंदिर बना दिया है। हैरानी की बात है कि रातभर में यह मंदिर लोहे और स्टील से बना दिया गया और पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय निकाय को भी इसका पता नहीं चला। सुबह मंदिर पहुंचे लोगों ने पहले तो दर्शन किए फिर जय श्रीराम और बजरंग बली के नारे भी लगाए। उधर, जानकारी मिलने पर

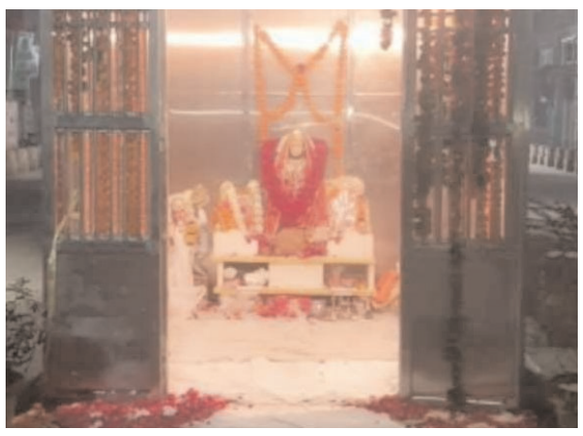

मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने मंदिर निर्माण को लेकर महंत से सवाल पूछे हैं। मसलन पूछा है कि मंदिर कब बना?किसने बनाया पीडब्ल्यूडी इस जमीन की मालिक है तो क्या उससे इजाजत ली क्या महंत यहां पूजा करने के लिए तैयार है यह भी बताया कि यह मंदिर निर्माण कोर्ट के आदेश की अवमानना है। इस पर महंत ने कहा कि जनता ने बनाया है। जनता ने ही आरती की। यह भी कहा कि किससे इजाजत ली यह तो जनता ही बताएगी, लेकिन सेंट्रल वर्ज पर मंदिर बन जाने से कोई यातायात प्रभावित नहीं होगा। शुक्रवार को हनुमान मंदिर के महंत पंडित अशोक शर्मा ने बताया कि सुबह चार बजे एक फोन आया कि आरती करने आ जाओ। मैं यहां पहुंचा तो मंदिर बना हुआ था। सुबह पांच बजे हमने आरती की है। किन लोगों ने बनाया मूर्ति कौन लेकर आया इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। शुक्रवार शाम को सात बजे हनुमान चालीसा का पाठ होगा और हनुमान आरती होगी। वहीं, शनिवार सुबह सुंदरकांड का पाठ होगा और भंडारा किया जाएगा। जागरण संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक, चांदनी चौक में जिस जगह पर हनुमान मंदिर तोड़ा गया था, वहां रातभर में स्थानीय लोगों ने फिर मंदिर बना दिया। जनवरी के पहले सप्ताह में चांदनी चौक सेंट्रल वर्ज पर यह मंदिर तोड़ा गया था, जिस पर उत्तर दिल्ली नगर निगम ने सफाई दी थी यह मंदिर तोड़ा नहीं गया, बल्कि यहां से हटाया गया है। यहां पर मंदिर हटाने के दौरान नगर निगम ने पीपल का पेड़ भी काट दिया गया था। वहीं, इसकी जानकारी लगते ही उत्तर दिल्ली नगर निगम के महापौर जय प्रकाश ने ट्वीट किया- चांदनी चौक में विराजे पवनसुत हनुमान जय श्री राम। आज दोपहर बजे दर्शन कर हनुमान मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करूंगा।

शिक्षक भर्ती परीक्षा में जातिगत प्रश्न पूछने पर कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की ओर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में दो बार जातिगत प्रश्न पूछने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्ति ने प्रश्न में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है।

वह भी एक बार नहीं, लगातार दूसरे वर्ष। प्रथम दृष्टया यह संज्ञेय अपराध है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस अधिनियम में सक्षम अधिकारी की ओर से मामले की जांच की जाए। उसकी मासिक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए।

अक्टूबर 2018 और अगस्त 2019 में डीएसएसएसबी ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति से जुड़े आपत्तिजनक प्रश्न पूछे थे। इस मामले में अधिवक्ता डॉ. सत्यप्रकाश गौतम ने अर्जी दायर कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया था कि अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान करने के लिए जानबूझ कर यह प्रश्न पूछे गए थे। इस मामले में डीएसएसएसबी की तरफ से कोर्ट को बताया गया था समिति से जांच कराने के बाद ये प्रश्न पत्र बनाने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यही नहीं, डीएसएसबी ने बंद लिफाफे में कोर्ट को उन लोगों की सूची सौंपी थी, जिन्होंने ये प्रश्न पत्र बनाए थे। अक्टूबर में सुनवाई के दौरान डीएसएसएसबी के चेयरमैन संतोष वैद्य ने इस मामले में खेद भी जताया था। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र बेदी की कोर्ट ने इस मामले में आरोपितों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

लॉकडाउन में पुलिस ने तीन करोड़ लोगों की मदद की, हर चुनौती का सामना किया

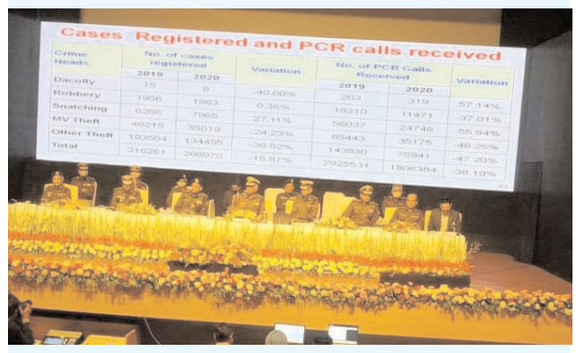

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस- दिल की पुलिस। दिल्ली पुलिस अपने कर्तव्य में इस वाक्य का पूरा-पूरा पालन कर रही है। मौका है दिल्ली पुलिस के वार्षिक प्रेसवार्ता का। यह जानकारी यहां पर कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले दिल्ली में दंगे हुए बाद में फिर कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। इस लॉकडाउन में पुलिस ने तीन करोड़ लोगों की मदद की गई। इस दौरान हर चुनौती का डट कर सामना किया। पुलिस आयुक्त ने आगे बताया कि साल 2020 में दिल्ली पुलिस ने विभिन्न चुनौती का सामना किया है।

कोरोना के कारण जब लॉकडाउन लगा तब कई प्रकार की परेशानी लोगों को हो रही थी मगर हमने आगे बढ़ कर उनकी मदद की। बुजुर्ग और बीमार लोगों को दवाईयां दीं। डेढ़ लाख कोरोना से बचाव के लिए दवा के पैकेट बांटे गए थे। इस दौरान अधिकतर चीजें ऑनलाइन हुईं। इस कारण साइबर क्राइम भी बढ़ा। साइबर ठग और क्रिमिनल एक्टिव ज्यादा हो गए थे। हालांकि हमने इसके रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर सफलता भी पाई। इतिहास के पन्नों में दिल्ली पुलिस की दरियादिली दर्ज हो गई है। कोरोना से जंग जीतने वाले पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा दान करके संक्रमितों की जान बचाई। इसकी सभी लोगों ने तारीफ भी की थी। कोरोना के दौरान पुलिस ने दवा के पैकेट बाटे थे।

दिल्ली दंगे में 755 एफआईआर हुई। इस मामले में 3 एसआईटी दिल्ली दंगे की जांच कर रही हैं। दंगाइयों को पहचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जिससे सफलता भी मिली है। दंगाइयों ने इंटरनेट मीडिया पर की गई चैट को डीलिट कर दिया था, पुलिस ने उसे रिकवर किया। पुलिस जांच की दंगे में किसके पास कितना पैसा आ रहा था इसका भी पता चला। पुलिस ने ऐसे प्रयास किए जिससे लोग उनसे जुड़े।

26 फरवरी को भारत बंद, सोमवार को देशभर के बाजारों में निकाला जाएगा ट्रेडर्स मार्च

नई दिल्ली। कंफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आरोप लगाया है कि मौजूदा वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतर व सरल कर प्रणाली की कल्पना के ठीक विपरीत है। यह जटिल है। चार वर्षों में इसके नियमों में करीब 950 संशोधन स्वयं तस्वीर बयां करते हैं। जीएसटी परिषद भी प्रणाली की स्थिरता को लेकर आश्वस्त नहीं है, लेकिन वह व्यापारियों से उम्मीद करता है कि वे इसके प्रविधानों का निर्बाध तरीके से अनुपालन करें अन्यथा जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद हो सकता है। इनपुट क्रेडिट से हाथ धोना पड़ सकता है और दंड भी भुगतना पड़ सकता है। पत्रकार वार्ता में कैट के अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि इस निराशाजनक पृष्ठभूमि में उनके संगठन ने 26 फरवरी को भारत व्यापार बंद का आह्वान किया है, जिसे व्यापारी व अन्य संगठनों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने एक बार फिर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण व जीएसटी काउंसिल से मौजूदा कर प्रणाली की समग्र समीक्षा कर उसे सरल और युक्तिसंगत बनाने की मांग की है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी परिषद हमेशा यह दावा करती है कि यह एक सरलीकृत कराधान प्रणाली है। यदि वास्तव में ऐसा है, तो हम परिषद के सदस्य सभी राज्य वित्त मंत्रियों को आमंत्रित करते हैं कि वे किसी भी सार्वजनिक मंच पर बिना किसी बाहरी मदद के जीएसटी रिटर्न फार्म भरकर दिखाएं। इससे जीएसटी कर प्रणाली के सरलीकरण के दावों और जटिलताओं की सच्चाई सामने आ जाएगी। इसी तरह जीएसटी नियमों में किए गए हाल के विभिन्न प्रविधान कठोर और मनमाने हैं, जो अधिकारियों को बेजा अधिकार देते हैं। इसमें कारण बताओ नोटिस जारी करने से इन्कार करने या कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अवसर न देने जैसे मामले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ हैं।

घायल कबूतर को बचाने में गई बच्ची की इज्जत, दोषी से कहा माफ कीजिए, जज बोले- तुम इस लायक नहीं

नई दिल्ली। बाल पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार से जुड़ा अपराध माफी के योग्य नहीं है। दोषी की सजा को कम करने और उसे रिहा करने से समाज में गलत संदेश जाएगा और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के जिन उद्देश्यों के लिए पाक्सो अधिनियम अधिनियमित किया गया है वह पूरा नहीं हो सकेगा। न्यायमूर्ति एस प्रसाद की पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए सात साल की बच्ची के साथ असहमति से बनाए गए यौन संबंध के मामले में दोषी जितेंद्र कुमार गोस्वामी की अपील याचिका खारिज कर दी। पीठ ने जितेंद्र को दोषी करार देने के तीस हजारी अदालत के 29 नवंबर 2017 के फैसले को बरकरार रखते हुए प्रथम अपीलकर्ता अदालत की टिप्पणी को सही ठहराया, जिसमें अदालत ने बच्ची के साथ किए गए अपराध के मामले में दोषी को दी गई दो साल

व छह महीने की सजा को कम बताया था।

न्यायमूर्ति एस प्रसाद की पीठ ने कहा कि दोनों ही अदालतों ने सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों को देखने के बाद उचित फैसला सुनाया है। निश्चित तौर पर मामले से जुड़ी फारेंसिंक रिपोर्ट आने में पांच साल का वक्त लगा है, लेकिन रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता दोषी नहीं है। अतिरिक्त लोक अभियोजक मीनाक्षी चौहान ने कहा कि दोनों ही निचली अदालतों ने पीड़ित बच्ची के बयान को सही माना है और उसके बयान पर भरोसा किया है।

वहीं, दोषी के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनका मुवक्किल पेशे से शिक्षक है और उसका परिवार है। निचली अदालत द्वारा दी गई 30 महीने की सजा में से 28 महीने की सजा उसने पूरी कर ली है। ऐसे में उसे राहत देते हुए उसकी बाकी की सजा को माफ कर दिया जाए।

याचिका के अनुसार जून 2012 में बच्ची जब छत पर खेल रही थी तो उसे एक घायल कबूतर मिला। बच्ची कबूतर को लेकर अपने एक दोस्त के पास गई और उससे पूछा कि क्या वह कबूतर को रख सकता है। इस पर उसके दोस्त ने मना किया और कहा वह जानता है कि कबूतरों को कौन रखता है। उसने दोषी जितेंद्र कुमार गोस्वामी के बारे में बच्ची को बताया। बच्ची जब कबूतर देने जितेंद्र के घर पहुंची तो उसने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देकर गलत काम किया।

भारत के खिलाफ साजिश की खुल रही नई-नई परतें, अशांति फैलाने के लिए विरोधियों ने मिलाए थे हाथ

नई दिल्ली। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, देश को अस्थिर करने व दुनियाभर में इसकी छवि खराब करने को लेकर रची जा रही साजिश की नई-नई परतें खुल रही हैं। पुलिस को अब एक और नई सनसनीखेज जानकारी यह मिली है कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थकों के संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन (पीजेएफ) के संस्थापक मो धालीवाल ने भारत में अशांति फैलाने के उद्देश्य से प्रतिबंधित संगठन सिख फार जस्टिस (एसएफजे) से हाथ मिलाया था। 2020 की शुरुआत में ही दोनों संगठन सामूहिक रूप से भारत में अशांति पैदा करने के लिए तरह-तरह के अभियान में जुट गए थे। अपनी साजिश में खालिस्तानी समर्थकों ने मुंबई की अधिवक्ता व जलवायु कार्यकर्ता निकिता जैकब के जरिये जानबूझकर जलवायु व पर्यावरण कार्यकर्ताओं को इसलिए जोड़ा, ताकि पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों को उनपर शक न हो। निकिता अहिंसक नागरिक असहयोग के जरिये पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारों पर दबाव बनाने वाले वैश्विक आंदोलन एक्सटिंक्शन रेबेलियन (एक्सआर) की सदस्य है। उसके संपर्क में देश-विदेश के कई जलवायु कार्यकर्ता हैं। विगत 14 फरवरी को मुंबई की रहने वाली जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार कर साइबर सेल ने उसे पूछताछ के लिए पांच दिनों के रिमांड पर लिया था। शुक्रवार को रिमांड की अवधि खत्म होने पर साइबर सेल दोबारा उसे रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। दिशा से अभी दिल्ली में ही पूछताछ की जा रही है, उसे बेंगलुरु भी ले जाया जाएगा।

संपादकीय

सुधरते हालात, लेकिन चिंता कायम

देश में कोविड-19 का प्रसार क्या थमता दिख रहा है? तथ्य बताते हैं कि हर दिन नए मामले अब 10 हजार से भी कम हो गए हैं। बीते सात दिनों का रोजाना का औसत 12 हजार से नीचे आ चुका है। इतना ही नहीं, पिछले दस दिनों से हर रोज कोरोना की जंग हारने वाले मरीजों की संख्या भी 150 से नीचे लाने में हम सफल हुए हैं। कल सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछले 24 घंटे में 15 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है, जिससे लगता है कि यह वायरस अब कमजोर पड़ने लगा है। ये आंकड़े निस्संदेह सुकूनदेह हैं, मगर इनसे यह भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि कोरोना महामारी बहुत जल्द अतीत बन सकती है। विशेषकर सांस संबंधी संक्रमण के बारे में यही कहा जाता है कि नए मामलों के सामने न आने के बावजूद कुछ वक्त तक बीमारी बनी रहती है। लिहाजा, हमें हरसंभव सावधानी बरतनी ही होगी। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना, दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करना व नियमित तौर पर साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक है। इसके साथ ही, 'ट्रेसिंग' (संक्रमित के संपर्क में आए तमाम लोगों की पहचान) पर भी हमें लगातार ध्यान देना होगा। कुछ देशों में यह भी दिखा है कि वायरस के 'म्यूटेट' (रूप में बदलाव) हो जाने से संक्रमण में अचानक तेज वृद्धि हुई है। अपने यहां भी यह खतरा बना हुआ है। चूंकि हरेक वायरस का यह नैसर्गिक गुण होता है कि वह अनुकूल माहौल मिलने पर म्यूटेट हो सकता है, इसलिए भारत में कोरोना वायरस का नया 'स्ट्रेन' दूसरे देशों से ही नहीं आ सकता, बल्कि यहां पर पैदा भी हो सकता है। यही कारण है कि वायरस की 'जेनेटिक' जांच, यानी उत्पत्ति संबंधी पड़ताल आवश्यक है, जिससे पता चलता है कि वायरस अगर अपना चरित्र बदल रहा है, तो वह कितना खतरनाक है। अच्छी बात है कि इस जांच में भारत को महारत हासिल है।

कोविड-19 के खिलाफ हमारी सफलता अब भी दूर है। जरूरत को देखते हुए आर्थिक गतिविधियां भले ही बढ़ाई जा चुकी हैं और बाजार में भीड़ भी दिखने लगी है, मगर एक सच यह भी है कि बिहार विधानसभा चुनाव अभियान का कोई खास नकारात्मक असर नहीं दिखा था, जबकि मतदान उस समय हुए थे, जब देश संक्रमण के शीर्ष पर था। सामान्य तौर पर यही दिखा है कि एशियाई देशों, खासकर दक्षिण एशियाई मुल्कों में न सिर्फ कोविड-19 संक्रमण का प्रसार तुलनात्मक रूप से धीमा रहा, बल्कि मौत भी कम हुई है। इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि एशियाई नागरिकों के शरीर में एक खास प्रोटीन पाया जाता है, जो कोरोना के कुछ रूप के खिलाफ खासा प्रतिरोधक साबित हुआ है। अगर यह निष्कर्ष वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरा, तो इसमें हम अपने लिए उम्मीद देख सकते हैं। हालांकि, मानव शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने वाले सीरो सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि देश की एक बड़ी शहरी आबादी इस रोग से सफलतापूर्वक लड़ चुकी है। इसीलिए आगे की हमारी रणनीति इन दो सवालों के आसपास बनेगी कि क्या कोई नया 'स्ट्रेन' हमारे देश में दस्तक दे चुका है? अगर हां, तो यह कितना घातक है या संक्रमण की इसकी क्षमता क्या है? और दूसरा सवाल, अभी हमने जो प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली है, उस पर वायरस का नया रूप कितना असरदार होगा? बात यदि शहरों की हो, तो यह नहीं मानना चाहिए कि ग्रामीण भारत को नजरअंदाज किया गया है। सीरो सर्वे से यह आशंका जताई जा सकती है कि ग्रामीण इलाकों में खतरा बना हुआ है, लेकिन यदि शहरों में ही संक्रमण को थाम लिया जाएगा, तो गांवों के लिए यह डर गलत साबित होगा। मगर हमारी यह उम्मीद भी तभी तक जिंदा रहेगी, जब तक कि इस वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा तय तमाम दिशा-निर्देशों का हम संजीदगी से पालन करते हैं। इसीलिए अब देशव्यापी लॉकडाउन के आसार कम नजर आते हैं। हां, किसी आपात स्थिति में इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर भी, आने वाले दिनों में अब छोटे-छोटे क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करके ही महामारी का मुकाबला किया जाएगा। इन दिनों कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि स्थानीय प्रशासन खुद सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन कराने को उत्सुक नहीं है, जबकि शुरुआती दिनों में इसके लिए पुलिस ने लाठियां तक पटकी थीं। इससे राजनीतिक जलसे या धार्मिक उत्सव जैसे बड़े आयोजन खतरे को न्योता दे सकते हैं। स्थानीय प्रशासन को पेशेवर रुख अपनाना पड़ेगा। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जरूरी सावधानियों का हरसंभव पालन किया जाए। अभी कुंभ स्नान के लिए भी मेला पास जारी करने की तैयारी चल रही है, जो एक अच्छी रणनीति है। इसी तरह, सार्स या मर्स की तरह कोविड-19 बीमारी के अचानक खत्म होने के दावे को भी सही नहीं माना जा सकता। अलग-अलग राष्ट्रों में इस वायरस का अलग-अलग पैटर्न दिखा है। यहां तक कि हमारे देश के अंदर ही अलग-अलग हिस्सों में इसके कई रूप मिले हैं। अपने यहां तो केरल में आज भी यह तेजी से लोगों को बीमार कर रहा है। लिहाजा, कोरोना वायरस का यह चरित्र आगे भी बना रहेगा। हां, एक बड़ी आबादी के इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेने से हम कहीं बेहतर स्थिति में हैं। ऐसे हालात में टीके से स्वाभाविक तौर पर उम्मीद बन जाती है। अभी जो निर्धारित किया गया है, उसके मुताबिक अग्रिम मोर्चे के तमाम कर्मियों के अलावा 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। हम सबसे तेज गति से टीकाकरण करने वाले देश हैं और पिछले 24 दिनों में ही करीब 58 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। फिर भी, प्राथमिकता सूची वाले वर्ग का टीकाकरण जून-जुलाई तक संभव है। इसके बाद विशेषज्ञ समूह तय करेगा कि किनको टीका लगाया जाएगा, किन्हें इसकी जरूरत नहीं है। अगर बिना टीका लगाए हालात संभलते हैं, तब भी विशेषज्ञ समूह के निर्णय पर ही हमें भरोसा करना चाहिए और उसी के मुताबिक टीका लगवाने का फैसला करना चाहिए।

प्रवीण कुमार सिंह

रचनात्मकता सूखी तो सोशल मीडिया पर अनावश्यक विवाद खड़ा करके चर्चा में बने रहने का सहारा

राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करने वालों से भी अक्सर इस तरह की भूल हो जाती हैं। राम भारतीय संस्कृति में इस तरह से रचे-बसे हैं कि उनके सामने कोई भी वाद अर्थहीन हो जाता है। राम के व्यक्तित्व का जो वैराट्य है वो धर्म, जाति, विचारधारा, तर्क आदि की परिधि से परे है। राम मंदिर निर्माण को किसी संकीर्ण दृष्टि से देखना या उस पर विवाद खड़ा करना अनुचित है। राम मंदिर पर उठने वाले तमाम विवादों को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले से विराम दे दिया था। उसके बाद ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ है।

हिंदी के एक कहानीकार हैं। नाम है उदय प्रकाश। उनकी लंबी कहानी 'मोहनदास' को साहित्य अकादमी ने उपन्यास मानते हुए पुरस्कृत किया था। उदय प्रकाश को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने वाली जूरी में अशोक वाजपेयी भी थे। ये वही अशोक वाजपेयी हैं जिनको कभी उदय प्रकाश ने 'भारत भवन का अल्सेशियंस' कहा था।

ये वही उदय प्रकाश हैं जिनको योगी आदित्यनाथ ने पहला 'नरेन्द्र स्मृति सम्मान' दिया था। जब उनको ये पुरस्कार मिला था तब हिंदी के कई लेखकों ने बयान जारी कर उनकी निंदा की थी। इनमें 'पहल' पत्रिका के संपादक ज्ञानरंजन के अतिरिक्त विद्यासागर नौटियाल, विष्णु खरे, भगवत रावत, मैनेजर पांडे, राजेन्द्र कुमार, इब्बर रब्बी, मदन कश्यप और देवी प्रसाद मिश्र जैसे वामपंथी लेखक शामिल थे। उस वक्त खूब विवाद हुआ था। इसके बाद उदय प्रकाश ने 2015 में पुरस्कार वापसी का शिगूफा छेड़ा था।

ये अलग बात है कि अभी तक वो अपनी पुस्तकों पर अपने परिचय में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक लिखते हैं। पुरस्कार वापसी का शिगूफा छोड़ने वाले उदय प्रकाश पहले लेखक थे लेकिन बाद में अशोक वाजपेयी और मंगलेश डबराल जैसे लेखकों ने इसको लपक लिया था और वो पुरस्कार वापसी अभियान के अगुआ माने गए थे। उदय प्रकाश इस बात को लेकर अपने वामपंथी साथियों से झुब्ध हुए थे कि पुरस्कार वापसी का पर्याप्त श्रेय उनको नहीं मिल पाया।

उदय प्रकाश ने लंबे समय से छिटपुट लघु कथाएं और कविताओं को छोड़कर कुछ लिखा नहीं। लेकिन चर्चा में बने रहने की कला में माहिर हैं। कभी रेत माफिया से जान का खतरा तो कभी हिंदी लेखक प्रभात रंजन के साथ इंटरनेट मीडिया पर

अनावश्यक विवाद खड़ा करके वो चर्चा में बने रहते हैं। उदय प्रकाश के बारे में इतना लिखने का औचित्य ये है कि वो एक बार फिर से विवादों में हैं। दरअसल पिछले दिनों उदय प्रकाश ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए चंदा दिया और उसकी रसीद अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दी। इस टिप्पणी के साथ कि 'आज की दान दक्षिणा'।

इसके नीचे कोष्ठक में लिखा 'अपने विचार अपनी जगह पर सलामत'। उनकी इस पोस्ट के बाद वामपंथी खेमे से विरोध के स्वर उठने लिखे। कई लोगों ने उदय प्रकाश का नाम लेकर तो कइयों ने बगैर नाम लिए उनपर पाला बदलने का आरोप लगाया। उदय प्रकाश के इस कदम को लेकर हिंदी साहित्य के कई लेखक अबतक उबल रहे हैं। कुछ ने तो सारी हदें पार करते हुए राम मंदिर तक पर मर्यादाहीन टिप्पणी कर डाली। इसके बाद राम मंदिर के पक्षधरों ने भी मोर्चा खोल दिया।

परिणाम ये हुआ कि उदय प्रकाश एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए। उदय प्रकाश हिंदी के एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने किसी जमाने में कुछ अच्छी कहानियां और कविताएं लिखी थीं। बाद में जब रचनात्मकता का सिरा उनके हाथ से छूटा तो वो साहित्येतर क्रियाकलापों से खुद को प्रासंगिक बनाने की जुगत में लग गए। कुछ सालों पहले इस बात की चर्चा हुई थी उदय प्रकाश अपना पहला उपन्यास लिखने जा रहे हैं। खुद लेखक ने भी इस आशय की बातें की थीं। उस वक्त कवि केदारनाथ सिंह जीवित थे, उन्होंने भी अपने एक साक्षात्कार में ये बात बताई थी कि उदय प्रकाश 'चीना बाबा' के नाम से एक उपन्यास लिख रहे हैं। साहित्यिक हलकों में तो इस बात की भी चर्चा थी कि उदय प्रकाश ने एक विदेशी प्रकाशन गृह से इसके प्रकाशन के लिए अनुबंध कर लिया है और उनको अग्रिम धनराशि भी मिल गई है। लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी अबतक हिंदी साहित्य जगत 'चीना बाबा' का इंतजार कर रहा है। इस बीच 'चीना बाबा' को लेकर कई तरह की बातें हिंदी प्रकाशन की दुनिया में होती रहीं। कभी किसी प्रकाशन से तो कभी किसी प्रकाशन से उसके प्रकाशित होने की चर्चा होती रही। इस बीच करीब दो साल पहले उनका एक कविता संग्रह 'अंबर में अबाबील' प्रकाशित हुआ था। इस कविता संग्रह को ना तो पाठकों ने पसंद किया और ना ही आलोचकों ने। हिंदी साहित्य जगत में तो इसकी चर्चा ही नहीं हुई।

पिछले दो साल से ही उनके नए कहानी संग्रह के प्रकाशन की चर्चा सुनाई दे रही है लेकिन वो भी अबतक प्रतीक्षित है। इन सालों में तात्कालिक घटनाओं पर उन्होंने जो खबरनुमा लघु कथाएं लिखी हैं वो भी अबतक इतनी नहीं हो पाई हैं कि जिसको एक संग्रह का रूप दिया जा सके। रचनात्मकता के स्तर पर चुक जाने के बाद उदय प्रकाश ने अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने के लिए या खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए राम के शरण में जाना तय किया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने चंदा दिया। राम मंदिर को चंदा देने को वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है।

राम को किसी वाद विशेष के अनुयायियों के आराध्य के तौर पर देखने वालों से इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करने वालों से भी अक्सर इस तरह की भूल हो जाती हैं। राम भारतीय संस्कृति में इस तरह से रचे-बसे हैं कि उनके सामने कोई भी वाद अर्थहीन हो जाता है। राम के व्यक्तित्व का जो वैराट्य है वो धर्म, जाति, विचारधारा, तर्क आदि की परिधि से परे है। राम मंदिर निर्माण को किसी संकीर्ण दृष्टि से देखना या उस पर विवाद खड़ा करना अनुचित है। राम मंदिर पर उठने वाले तमाम विवादों को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले से विराम दे दिया था। उसके बाद ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ है। मंदिर का निर्माण पूरे देश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो रहा है। ऐसे में एक वामपंथी लेखक का प्रभु श्रीराम के अयोध्या में निर्मित हो रहे मंदिर के लिए योगदान करना कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर विवाद खड़ा किया जाए। वो उनकी आस्था है। यहां यह याद दिलाना उचित होगा कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में नामवर सिंह की ईश्वर में आस्था सार्वजनिक हुई थी।

लेकिन उदय प्रकाश ने जिस तरह से मंदिर के लिए दिए गए चंदे की रसीद को सार्वजनिक किया उसको लेकर प्रश्न उठाना सही है। लेकिन वामपंथी लेखक प्रश्न इस बात पर नहीं खड़े कर रहे हैं, उनको आपत्ति इस बात को लेकर है कि उदय प्रकाश ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा क्यों दिया? यह अनायास नहीं है कि उदय प्रकाश जैसे विवादाचार्य वामपंथ की इन कमजोरियों का फायदा उठाकर खुद को चर्चा में बनाए रखने का उपक्रम करते हैं। उदय प्रकाश को ये बखूबी पता रहा होगा कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने से वामपंथी नाहक विवाद खड़ा करेंगे। हुआ भी वैसा ही।

दरअसल भारत के वामपंथी बुद्धिजीवी अबतक ना तो भारत को समझ पाए हैं और ना ही भारतीय मानस को। अगर भारतीय मानस को समझ जाते तो प्रभु श्रीराम के मंदिर निर्माण को लेकर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियां नहीं करते। समझ तो वो भारतीय संस्कृति को भी नहीं पाए, अगर समझ पाते तो राम मंदिर को किसी खास विचारधारा या खास राजनीतिक दल से जोड़कर देखने की गलती नहीं करते।

आर्थिक गतिविधियों को तेजी प्रदान करने के लिए न्यायिक व प्रशासनिक सुधारों पर जोर देने का समय

हमारे देश की राजनीति में रोजगार की समस्या विमर्श के केंद्र में नहीं दिखती है। अगर कहीं बेरोजगारी पर सार्वजनिक रूप से चर्चा भी होती है, तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अभी वर्तमान में भले ही इस मुद्दे को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही हो, परंतु भविष्य में पूरे देश में रोजगार की समस्या का मसला भयावह रूप धारण कर सकता है। हालांकि, पूंजीवादी व्यवस्था का विकास निश्चित रूप से इस तरह के सामाजिक मुद्दे से बचने की भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन हमारे संघीय ढांचे की व्यवस्था के कारण देश में अब तक सामाजिक मुद्दे को प्राथमिकता मिलती रही है।

आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही भयावह होने वाली है, क्योंकि हमें यह ज्ञात है कि कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। परंतु इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इससे पूर्व भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत नहीं थी। यह सर्वविदित तथ्य है कि अर्थव्यवस्था गिरने का सीधा प्रभाव सामाजिक स्तर पड़ता है। कोई भी क्षेत्र या समूह इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहता है। ऐसे में युवाओं और रोजगार सृजन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

वास्तविकता तो यह है कि देश में कोरोना के असर के पहले से ही बेरोजगारी प्रतिशत बढ़ता जा रहा था। युवा इसे महसूस भी कर रहे थे, लेकिन देश के अधिकांश राजनीतिक दलों ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2019 के

लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकांश राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में भी रोजगार मुद्दे को खास महत्व नहीं दिया गया। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि रोजगार के लिए अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। देश में उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था संभलती हुई जरूर दिखी। हालांकि वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं से जुड़ने से रोजगार के नए अवसर अवश्य मिले, लेकिन यह टिकाऊ व्यवस्था बनती हुई नहीं दिख रही है। जिस विदेशी निवेश के सहारे अर्थव्यवस्था को संभालने और रोजगार पैदा करने की नीतियों को अपनाया गया था, उसका परिणाम अलग ही देखने को मिलने लगा। उदारीकरण की नीतियों से निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाने लगा और सार्वजनिक क्षेत्र के जो बड़े उपक्रम रोजगार सृजन करते थे, उनकी भागीदारी धीरे धीरे कम होने लगी। इस नीति ने न केवल विदेशी पूंजी का आयात किया, बल्कि घरेलू पूंजीपतियों को भी बढ़ावा दिया। लिहाजा पिछले दशकों से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अनेक भारतीय पूंजीपतियों का नाम भी शामिल हो रहा है। निजी हाथों में पूंजी के संकेंद्रण ने राज्य के हाथों में रोजगार देने की क्षमता छीन ली।

नौकरियों में स्थायित्व की जगह संविदा और ठेके की व्यवस्था होती जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी स्थायी नौकरी की जगह अस्थायी नौकरी की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार की राह आज मुश्किल दौर में है। ऐसे में समय आ गया है जब सरकार को रोजगार को लेकर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और स्वरोजगार के लिए एक स्पष्ट खाका बनाना चाहिए। स्वरोजगार में भी पारदर्शिता के साथ युवाओं को अपनी क्षमता और योग्यता के हिसाब से विभिन्न सेक्टरों में अभिरुचि के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

देश में बढ़ती बेरोजगारी से युवाओं में असंतोष तो पैदा होता ही है, साथ में यह भी मांग करता है कि रोजगार के विषय पर देश में खुलकर बहस हो और राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों में इसे मुख्य एजेंडे के तौर पर शामिल किया जाए। साथ ही, इस पर अमल करते हुए यह बात सुनिश्चित हो कि देश में रोजगार के तमाम नए अवसर सृजित किए जाएंगे, ताकि युवाओं को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो। सभी को यह समझना होगा कि देश का युवा खुश एवं समृद्ध होगा, तब जाकर देश तरक्की के नए आयाम को हासिल कर सकेगा।

न्याय तंत्र की मुसीबतें

पिछले दिनों आई इंडियन जस्टिस रिपोर्ट हमें मौजूदा विधि व्यवस्था से जुड़े उन बुनियादी मुद्दों से रूबरू कराती है जो आम तौर पर अनदेखे ही रह जाते हैं। देश की न्याय प्रक्रिया की गड़बड़ियों और इसके नतीजों के उदाहरण हमें मिलते रहते हैं। कभी अदालतों के असंगत फैसले के रूप में तो कभी सही फैसला आने में हुए अत्यधिक विलंब के रूप में, कभी पुलिस ज्यादतियों के रूप में तो कभी जेल प्रशासन की लापरवाही के रूप में। इन सबके मूल कारणों पर बातचीत कम होती है। देश में अपराध नियंत्रण और दंड विधान से जुड़ी पूरी मशीनरी किस हाल में है और किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, इस पर नियमित सार्वजनिक चर्चा संभवत- इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारा ध्यान आम तौर पर तात्कालिक महत्व की चौंकाने वाली घटनाएं ही खींचती हैं, और यह सवाल किसी तात्कालिक घटना से नहीं जुड़ा है। इसी कमी को पूरा करते हुए इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 बताती है कि कैसे हमारा यह तंत्र अपने ही बोझ से चरमरा रहा है। न्यायपालिका में लंबित मामलों की विशाल संख्या की तो बात ही छोड़िए, रिपोर्ट के मुताबिक जनरल केस क्लियरेंस रेट भी ऊपरी और निचली अदालतों में गिरता जा रहा है। और यह स्वाभाविक भी है। सुनवाई तो तब होगी जजों की संख्या पर्याप्त हो। लॉ कमिशन ने 1987 में ही अपनी 120वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि देश में 20,000 की आबादी पर एक जज का अनुपात होना चाहिए। हकीकत यह है कि आज भी 50,000 की आबादी पर एक जज का अनुपात बैठता है। राष्ट्रीय औसत के मुताबिक हाईकोर्टों में जजों के 38 फीसदी पद खाली पड़े हैं। पुलिस की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। एक लाख की आबादी पर 156 पुलिसकर्मी का अनुपात बैठता है। जनवरी 2020 की हालत रिपोर्ट में यह बताई गई कि राष्ट्रीय स्तर पर हर तीन जरूरी पुलिसकर्मियों में से एक का पद खाली था। यह तो हुई संख्या की बात। गुणवत्ता पर चर्चा करें तो उसकी एक अहम कसौटी डायवर्सिटी को माना जाता है। इस लिहाज से महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मामला बहुत ही चिंताजनक है। पुलिस में महिलाओं की मौजूदगी का राष्ट्रीय औसत 10 फीसदी है। सिर्फ आठ राज्य ऐसे हैं जहां पुलिस बलों में महिलाओं का अनुपात इससे बेहतर है। अदालतों में भी हर स्तर पर महिलाओं की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों के हाईकोर्टों में महिलाओं का औसत शून्य है। जाहिर है, ऐसी स्थिति में पुलिस और अदालतों से महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की सीमित अपेक्षा ही की जा सकती है। काम के बढ़ते बोझ और काम निपटाने वाले हाथों की लगातार कमी के बीच न्याय तंत्र के लिए ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं रह पाती। ऐसे में अगर जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से कहीं अधिक बनी हुई है और उनमें 70 फीसदी कैदी विचाराधीन हैं, जिनके बारे में यह भी पता नहीं है कि वे दोषी हैं या बेकसूर, तो आश्चर्य कैसा!

भारत-नेपाल के संबंध सैकड़ों वर्ष पुराने, चीन डाल रहा खटास

भारत वहां के प्रतिभाशाली बच्चों की सहायता कर एक रास्ता खोल सकता है। दरअसल ये बच्चे नेपाल में आगे चलकर अहम पदों पर काबिज होंगे, तो भारत के प्रति उनके मन में स्वाभाविक झुकाव होगा। भारत को इस मौके को भुनाना चाहिए। कूटनीति के अन्य प्रयासों के बीच सॉफ्ट कूटनीति को तेज करना चाहिए।

भारत-नेपाल के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान हों। नेपाल में यह संदेश भी पहुंचना चाहिए कि चीन नेपाल को श्रीलंका की तरह ऋण जाल में फंसाकर उसकी जमीन पर अधिकार कायम करने की रणनीति पर काम कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भारत-नेपाल सीमा पर नो मैन्स लैंड की पट्टी इतनी संकरी दिखती है कि दो देशों की सीमाओं में अंतर करना मुश्किल है। नेपाल की ओर बनी एक झोपड़ी में चांगमा (मिनी ट्रैक्टर की तरह) पर आंखें टिकती हैं। यह वहां चीन के बढ़ते प्रभाव की तस्वीर है। इसके मालिक बताते हैं कि भारत में ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो जोताई के लिए यह ले लिया। यह बात दूसरा अर्थ भी रखती है कि भारत से कटुता के दौर में नेपाली चीन की ओर भी नजर रखते हैं।

दरअसल भारत-नेपाल संबंधों का एक दौर वसंत के खिलते फूलों की तरह रहा है, जो पिछले कुछ दशकों में मुरझा से गए हैं। मजबूत दोस्ती के दौर वाले वर्ष 1950 में भारत और नेपाल के बीच मैत्री संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और नेपाल की ओर से शासक वीरेंद्र विक्रम शाह ने दस्तखत किए गए। इसने हिमालय की गोद में बसे छोटे देश को चीन की साम्राज्यवादी नीति से सुरक्षा प्रदान की।

लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ भूमि से घिरे देश को आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए राह प्रदान की गई। साथ ही भारत की वरीयता में पड़ोसी राष्ट्र की सुरक्षा और चीन का खतरा अहम था, इसलिए वह इस पर ही नजर रखे रहा कि नेपाल भारतीय हित के विपरीत कोई कार्य न करे। इसके बावजूद संधि का एक बिंदु नेपाल को खटकने लगा कि वह बिना भारतीय अनुमति

के विदेशों से हथियार की खरीद नहीं करेगा।

पिछली सदी के नौवें दशक में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान नेपाल ने संधि की परवाह न कर दूसरे देशों से हथियार खरीदने शुरू कर दिए। ऐसे में राजीव सरकार ने नेपाल के जरूरी सामान मंगाने वाले रास्तों को रोक पेट्रोलियम आपूर्ति को बंद कर दिया। वहां जरूरी सामान की किल्लत हो गई। ऐसे में विदेशी इशारे पर चलने वाले नेपाली राजनेताओं के एक वर्ग ने जनता को भारत विरोध के लिए उकसाना शुरू कर दिया। चीन को यहां से पूरा मौका मिल गया। हालांकि इस दौर में नेपाली राजशाही के भारत से नजदीकी संबंधों के चलते रिश्ते की इमारत ऊपर से तो सलामत बची रही, लेकिन आंतरिक रूप से दरारें पड़ गईं।

नेपाल नरेश वीरेंद्र की मौत के बाद राजशाही की जड़ें कमजोर हो गईं। चीन ने वहां माओवादियों की मदद बढ़ाकर राजशाही के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। जनता की ओर से भी लोकतंत्र की मांग तेजी से उठने लगी। भारतीय रणनीतिकार एक लोकतांत्रिक देश से ज्यादा मजबूत रिश्तों की सोचकर लोकतंत्र के समर्थन में आगे बढ़ गए। परंतु इससे भारतीय हितों की रक्षा नहीं हो सकी।

लोकतांत्रिक चुनावों के बाद सत्ता कम्युनिस्टों के हाथ में पहुंच गई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड के पहले ही कदम से उनका रुख भी जाहिर हो गया। पूर्व में जहां कोई भी नेपाली प्रधानमंत्री पहले भारत की यात्र करता था, वहीं प्रचंड पहले चीन गए। यह भारत के लिए एक झटका था। चीन के दबाव में प्रचंड भारतीय हितों की परवाह न कर उसके बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देते रहे। परंतु चीन मदद के दांव चलता है तो उसमें भी घात होता है। उसने श्रीलंका की तरह ही नेपाल को भी कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उस दौर में भारत बहुत कुछ कर पाने में समर्थ नहीं था और यह स्थिति अब तक कायम है। ऐसे में भारत के लिए अब उम्मीद की किरण दिख रही है।

कम्युनिस्ट पार्टी में केपी ओली और प्रचंड के अलग होने के बाद एक बार फिर राजशाही की मांग उठ रही है, तो नेपाल की जनता का एक धड़ा इस बात से भी नाराज है कि चीन राजनीतिक हस्तक्षेप कर हदों को पार कर गया है। ऐसे में भारत को नेपाली कांग्रेस की मजबूती पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं कम्युनिस्टों में प्रचंड को भी अपने पाले में लाने की जरूरत है। भारत में पढ़ाई के चलते उनकी भावनाएं यहां से जुड़ाव रखती हैं। साथ ही केपी ओली के प्रति चीन के झुकाव के चलते उनका इस ओर बढ़ना थोड़ा आसान भी होगा।

भारत को नेपाल में निचले स्तर पर भी संबंध मजबूती का काम करना चाहिए। चीन नेपालियों को मंदारिन भाषा पढ़ाने के लिए बड़ा बजट प्रदान करता है। भारत की ओर से हिंदी के लिए भी ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। नेपालियों और भारतीयों के बीच रोटी-बेटी के रिश्तों पर भी तेजी से काम करने की जरूरत है। भारत में सेना और नौकरियों में स्थान पाने वाले नेपाली जब वापस नेपाल पहुंचें तो हमारे राजदूत की तरह काम करें, इसके लिए उन्हें तैयार करने को भी कदम बढ़ाने चाहिए।

नेपाल में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। भारत वहां के प्रतिभाशाली बच्चों की सहायता कर एक रास्ता खोल सकता है। दरअसल ये बच्चे नेपाल में आगे चलकर अहम पदों पर काबिज होंगे, तो भारत के प्रति उनके मन में स्वाभाविक झुकाव होगा। भारत को इस मौके को भुनाना चाहिए। कूटनीति के अन्य प्रयासों के बीच सॉफ्ट कूटनीति को तेज करना चाहिए।

भारत-नेपाल के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान हों। नेपाल में यह संदेश भी पहुंचना चाहिए कि चीन नेपाल को श्रीलंका की तरह ऋण जाल में फंसाकर उसकी जमीन पर अधिकार कायम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इससे वहां भारत के प्रति सकारात्मक भाव बना रहेगा।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

उत्तर प्रदेश सरकार तथा आईकिया के बीच एमओयू, आएगा करीब पांच हजार करोड़ का निवेश

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीडन की फर्निशिंग कंपनी आईकिया के साथ शुक्रवार को बड़ा अनुबंध किया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर नोएडा अथॉरिटी तथा आईकिया के बीच विनिमय समारोह आयोजित किया गया। आईकिया इसके तहत नोएडा में करीब पांच हजार करोड़ रुपया का निवेश करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ शुक्रवार को आईकिया के समझौता के तहत कंपनी नोएडा में पांच हजार करोड़ से अधिक के निवेश लाएगी। कंपनी ने सेक्टर 51 में लगभग 12 एकड़ जमीन ली है। विकास और निर्माण कार्य कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाएगा।

सीएम योगी ने इस अवसर पर नोएडा अथॉरिटी के साथ ही व आईकिया को भी शुभकामना तथा बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज भूमि हस्तांतरण एवं लीज डीड विनिमय समारोह के अवसर पर मैं दोनों संस्थाओं को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आईकिया देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल नोएडा में निवेश को मूर्त रूप देने जा रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना अथॉरिटी क्षेत्र भारत में निवेश की सबसे अधिक संभावनाओं वाला क्षेत्र है। दुनिया के सबसे अच्छे निवेश के प्रस्ताव हमारे पास निरंतर आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने में और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने में सफलता अर्जित की है। इसके साथ ही साथ प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश को भी आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आईकिया से जुड़े अधिकारियों को एक बार फिर से आश्वस्त करता हूं कि यह निवेश आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। यह ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जहां एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि

आईकिया, जन सामान्य के लिए न केवल शॉपिंग मॉल, ऑफिस, होटल, रिटेल आउटलेट आदि के निर्माण की कार्यवाही समय सीमा में करेगी बल्कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य शहरों में भी निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगी। मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 5,500 करोड़ के निवेश के साथ लगभग 850 करोड़ की लागत से भूमि स्थानान्तरण से संबंधित कार्यवाही प्रदेश में डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी निवेश अनुकूल, पारदर्शी एवं व्यवस्थित नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में उद्यम अनुकूल स्थितियों के सृजन में सफलता प्राप्त की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के राष्ट्रीय क्रमांक में उत्तर प्रदेश का दूसरे स्थान पर होना इसकी पुष्टि करता है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, न केवल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है अपितु देश के सबसे अधिक युवा भी उत्तर प्रदेश में ही हैं, देश का सबसे बड़ा मार्केट भी उत्तर प्रदेश है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आईकिया द्वारा नोएडा में विकास के नए युग का सूत्रपात हो रहा है।आईकिया अपने आप में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास से संबंधित तमाम सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में भी इन्हें महारथ हासिल है। प्रदेश के अंदर हम लोग न केवल निवेशपरक और रोजगार उन्मुखी उद्यमों की स्थापना की दिशा में मजबूती से कदम उठा सकें बल्कि अधिक से अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी आर्जषित कर सकें, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार के उठाए गए कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मैं एवं आईकिया को इस एमओयू के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारी अथॉरिटी भी निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए कार्य करेगी।

विश्व की विख्यात स्वीडन की घरेलू फर्निशिंग रिटेलर कंपनी आईकिया अपने भारत संचालन में 10,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। इसी के तहत नोएडा में पांच हजार करोड़ का निवेश हो रहा है। आईकिया ने इससे पहले हैरादाबाद में अपने स्टोर खोले हैं। इसके बाद इनका नवी मुंबई में निवेश की योजना है। कंपनी के प्रतिनिधि ने इस अवसर पर कहा कि हमने एक अल्पकालिक उद्देश्य निर्धारित किया है कि 2022 तक भारत में हम कम से कम 100 मिलियन लोगों के पास अपने उत्पाद पहुंचा सकें। देश का पहला आइकिया स्टोर 2018 में हैदराबाद में खोला गया था। दुनियाभर में मशहूर स्वीडन का फर्नीचर मेगा स्टोर आईकिया अब नोएडा में अपना विस्तार करेगा।

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के नाम से बनाई फर्जी वेबसाइट, क्कककोड बदलकर लिंक किया खाता

अयोध्या । श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एकबार फिर जालसाजों के निशाने पर है। निधि समर्पण अभियान के बीच ट्रस्ट की फर्जी वेबसाइट बना कर ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र की ओर थाना रामजन्मभूमि में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह प्रकरण गत 30 जनवरी को प्रकाश में आया था, जिसकी छानबीन पुलिस कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसमें साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। कुछ सुराग हाथ लगे हैं।

ट्रस्ट की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में उल्लेख किया गया है कि श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अधिकृत वेबसाइट को ट्रस्ट की आवश्यक जानकारी देने के लिए बनाया गया है। मंदिर के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर ट्रस्ट के बैंक खाते एवं सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसी जालसाज ने ट्रस्ट की अधिकृत वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर उस पर ट्रस्ट के बैंक खाता एवं क्रिक रिस्पांस (क्यूआर) कोड बदल कर स्वयं का खाता नंबर व क्यूआर कोड प्रदर्शित कर दिया। फर्जी वेबसाइट के क्यूआर कोड को स्कैन करने पर खाताधारक का नाम तेजवीर सिंह सामने आया है, जबकि संबंधित खाता गौरव कुमार के नाम रजिस्टर्ड है। थाना प्रभारी रामजन्मभूमि राहुल कुमार ने बताया कि छानबीन की जा रही है। जल्द ही जालसाजों को गिरफ्तार किया जाएगा।

पहले भी साजिश का शिकार हो चुका है ट्रस्ट-

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहले भी साजिश का शिकार हो चुका है। गत वर्ष सितंबर माह में ट्रस्ट का फर्जी चेक तैयार कर छह लाख रुपये पार कर दिए गए थे। पुलिस ने गत 20 दिसंबर को चार शातिर लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मुंबई का गिरोह शामिल था। पकड़े गए लोगों में मुंबई के थाना फोर्ट बाजार गेट महापला हाउस निवासी प्रशांत महावल, थाणे जिला अंतर्गत डोमिबली ईस्ट प्रिमिया जेविंग फ्लैट निवासी विमल लल्ला, विष्णुनगर निवासी संजय तेजराज जैन व कोलासा निवासी शंकर सीताराम गोपाले शामिल थे।

संक्षिप्त खबर

विधायक मुख्तार अंसारी के घर का नक्शा पास करने वालों की सूची तलब, शासन के आदेश से एलडीए में खलबली

लखनऊ । चारबाग अग्निकांड के बाद माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के डालीबाग भवन का मानचित्र पास करने वाले लविप्रा के अभियंताओं की सूची तलब की गई है। विशेष सचिव आरपी सिंह द्वारा सूची मांगते ही लविप्रा में हड़कंप मच गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि नियम विरुद्ध मानचित्र स्वीकृत करने एवं निरस्त करने वाले अधिकारी व कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर 20 फरवरी तक शासन को उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में गृह विभाग ने पूरी रिपोर्ट लविप्रा से तलब की है। इसमें मुख्य रूप से निष्क्रांत संपत्ति डालीबाग से जुड़े भवनों के नक्शे शामिल किए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि ये भवन सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं और इनके नक्शे लविप्रा लविप्रा के अफसरों और कर्मचारियों ने गलत तरीके से पास किए थे। गृह विभाग के विशेष सचिव आरपी सिंह ने मंडलायुक्त रंजन कुमार को पत्र लिख कर पूरी रिपोर्ट रिपोर्ट तलब की है. मंडलायुक्त की ओर से ये पत्र प्राधिकरण भेजा गया है। अब प्राधिकरण में सूची तैयार की जा रही है। इसे एक से दो दिन में भेजने की तैयारी है। पत्र में राबिया बेगम जो कि मुख्तार अंसारी की मां है। उनके नाम भवन भूखंड संख्या 93 भाग, 21-188 व 93 राजा राममोहन राय डालीबाग तिलक मार्ग बटलरगंज के पास किए गए भवन निर्माण को अवैध बताया गया है। इसके अलावा अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम दर्ज भूखंड संख्या 14 बी 7 डालीबाग के मानचित्र को पास किए जाने के जिम्मेदारों को तलाशने के लिए पत्र लिखा है। इस भवन के मानचित्र को प्राधिकरण ने निरस्त भी कर दिया है।

कंपाउडिंग कराकर 2007 में पास कराया था नक्शा- मुख्तार अंसारी ने फरहत अंसारी के नाम पर डालीबाग में मकान पहले बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनवाया था।फिर रसूख के बल पर लविप्रा से नक्शा पास करवाया। यह कंपाउंडिंग मैप साल 2007 में पास करवाया गया था।

लखनऊ में शोहदे ने सरेराह छात्रा को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपित गिरफ्तार

लखनऊ । इंटरनेट मीडिया पर गुरुवार को एक छात्रा की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक स्कूल ड्रेस में जा रही छात्रा को रोककर बेरहमी से उसकी पिटाई करते नजर आ रहा है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर राजधानी पुलिस हरकत में आई। इंस्पेक्टर पीजीआइ आशीष कुमार द्विवेदी के मुताबिक वीडियो पुराना है, जिसे आरोपित ने वायरल किया था। छात्रा की दोस्त की तहरीर पर आरोपित कल्ली पश्चिम निवासी विकास रावत के खिलाफ कई धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई है। आरोपित विकास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छानबीन में सामने आया है कि आरोपित कार से छात्रा के पास पहुंचा था। इस दौरान आरोपित के साथ उसका साथी भी मौजूद था। विकास ने कार से उतरने के बाद छात्रा की पिटाई की थी। बीचबचाव करने आई पीड़िता की सहेलियों से भी आरोपित ने अभद्रता की थी। इस दौरान विकास के दोस्त ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाया था। कुछ माह पूर्व इस प्रकरण से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ था। पीड़ित छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने विकास के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।

पुलिस का कहना है कि आरोपित ने छात्रा को ब्लैकमेल करने के लिए उसी प्रकरण का दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इंटरनेट मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोगों ने आपत्ति जताई और आरोपित के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। पुलिस इस वीडियो का एक साल पुराना बताकर कार्रवाई से पल्ला झाड़ रही थी। हालांकि दबाव बनता देख पुलिस हरकत में आई और आरोपित को दबोच लिया।

बेलागंज में यमुने नदी किनारे बोरे में मिला महिला का शव, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

बेलागंज (गया)। गया जिले के बेलागंज थानाक्षेत्र के सोनपुर स्थित यमुने नदी घाट के समीप बोरा में बंद एक महिला की लाश को स्थानीय पुलिस ने बरामद किया। प्रथम दृष्ट्या में साक्ष्य छुपाने के लिये अन्यत्र हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिये उक्त स्थल पर हत्यारों ने फेंक दिया। शव की पहचान नही हो पायी है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए एएनएमसीएच भेज दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार की सुबह आस पास गांव के लड़के नदी में विसर्जित मूर्ति से उपयोगी समान ढूढ़ रहे थे। उसी दौरान मिट्टी से सना एक बोरा दिखायी दिया। जिसे लड़को ने मूर्ति समझ बाहर निकाला तो बोरा में एक लाश नजर आयी। जिसे देख लड़को ने हल्ला करना शुरू कर दिया। वहाँ सुबह टहल रहे लोगों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाना को दिया। जहां मौके पर पहुंच थानाध्यक्ष सूर्यवीर गुप्ता ने शव से भरे बोरी को नदी से बाहर निकलवाया। जिसमे लगभग 28 वर्ष की एक सावली महिला जो काले रंग की साड़ी पहने मिली। जिसमें बदबू के जिससे देखने से प्रत्तित होता हैं कि उक्त महिला की हत्या दो-तीन दिन पूर्व कही अन्यत्र कर दी गयी थी।और साक्ष्य छुपाने के नियत से बोरी में बंद कर उक्त सुनसान स्थल पर नदी में मिट्टी के अंदर कर दिया

बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू, तेजस्वी ने किया पेट्रोल-डीजल की कीमत पर सरकार को घेरने का एलान

पटना । बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज यानी शुक्रवार से शुरू हो चुका है। विपक्ष में शामिल राजद, कांग्रेस, भाकपा माले जैसी पार्टियों ने किसान आंदोलन और पेट्रोल-डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमत पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में शांति दिखी। हालांकि इससे पहले माले के विधायक ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर किसान आंदोलन को समर्थन दिया।

सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में राज्यपाल फागू चौहान ने सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए कृतसंकल्पित है। इसके लिए हर तबके को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। वृद्धजनों के लिए बिहार में आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। महिलाओं को रोजगार के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा। छात्राओं को 50 हजार रुपये तक की मदद सरकार उपलब्ध कराएगी।

बिहार के हर व्यक्ति को कोरोना का टीका मुफ्त- राज्यपाल ने कोरोना काल में नागरिकों की बेहतरी और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार के हर व्यक्ति को कोरोना का टीका मुफ्त दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के हर पांच गांव पर एक अस्पताल होगा। प्रदेश में नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे।

सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना- सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले से राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। वह सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते। ऐसे में पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमत को लेकर राजद ने विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस के कुछ विधायक मिट्टी का चूल्हा लेकर विधानसभा में पहुंचे हैं। वहीं भाकपा माले के विधायक किसान आंदोलन के समर्थन में तख्तियां लेकर सदन परिसर में पहुंचे।

जनता की भलाई नहीं, लड़ाई के लिए है यह सरकार : तेजस्वी

बजट सत्र में शिरकत करने शुक्रवार को दिल्ली से पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंहगाई के मुद्दे पर राज्य सरकार को फिर घेरा। कहा कि लोग सरकार को इसलिए चुनते हैं कि उनकी समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन यह सरकार जनता से ही लड़ाई कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोग महंगाई से परेशान हैं। नौजवानों, छात्रों एवं किसानों सबको ज्यादा दिक्कत है। सत्तारूढ़ दलों ने चुनाव में 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, जिसपर मुख्यमंत्री अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहले से ही देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कच्चा तेल सस्ता है, परंतु पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। इन सारे मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा।

श्याम रजक ने कहा- बढ़ती महंगाई से त्रस्त है जनता- राजद के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से महंगाई चरम पर है। नागरिक त्रस्त हैं। इस मुद्दे को विधानसभा के सत्र में राजद पुरजोर तरीके से उठाएगा। रजक गुरुवार को गायघाट लड्डू अखाड़ा के समीप गांधी सेतु के नीचे राजद द्वारा आयोजित धरना सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आबादी के बीच से गुजरे खुले सैदपुर-पहाड़ी नाला को भूमिगत कर इस पर सड़क निर्माण करने की मांग की। पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पटना को स्मार्ट बनाने की केवल बात करती है। इस पर काम हो तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी।

विरोध की आंधी में भी भाजपा ने मौजूदगी दर्ज कराई

चंडीगढ़ । पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब रही। इसके साथ ही पार्टी ने राज्य की सियासत के लिए अपने संकेत भी दे दिए। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने और किसान विरोध के बीच भाजपा ने आठ नगर निगम के चुनाव में 20 और 109 नगर काउंसिल में 29 सीटों पर हासिल पर जीत हासिल की। शिअद से गठबंधन टूटने के बाद उसने यह पहला चुनाव लड़ा। भारी विरोध और हमलों के बावजूद वह इस चुनाव में 60 फीसद सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने में सफल रही। भाजपा इस बात को लेकर राहत महसूस कर रही है कि राज्य में कृषि कानून बिलों को लेकर जिस प्रकार से उसका विरोध हो रहा था, उस स्थिति में भी भाजपा का खाता खुलना ही बड़ी बात है। वहीं, पार्टी की चिंता यह है कि मुकेरियां, होशियारपुर, दसुआ, पठानकोट जैसे क्षेत्र जोकि भाजपा के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। वहां पर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।

भाजपा के प्रदेश प्रधान अश्वनी शर्मा कहते है, निश्चित रूप से निकाय चुनाव में भाजपा के लिए खासी चुनौती भरा था। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भाजपा को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रखा था। भाजपा पहली बार अकेले दम पर चुनाव मैदान में थी। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भाजपा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब रही।

अहम पहलू यह है कि कृषि कानूनों को लेकर पूरे पंजाब में भाजपा नेताओं पर हमले हुए। यहां तक की भाजपा के प्रदेश प्रधान अश्वनी शर्मा, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला समेत वरिष्ठ नेताओं पर हमले हुए। किसान व किसान समर्थकों ने भाजपा के प्रचार अभियान को रोका, वहीं कई जगह पर तो भाजपा के दफ्तर को भी नहीं खुलने दिया। भाजपा के लिए परेशानी वाली बात यह भी थी कि कृषि कानूनों को लेकर लोगों में इतना गुस्सा देखने को मिला कि भाजपा के उम्मीदवारों को लोगों ने अपने घरों से भी भगा दिया। तमाम विरोध के कारण भाजपा को सभी काउंसिलों में उम्मीदवारों को खड़ा करना भी मुश्किल हो गया था।

भाजपा के महासचिव सुभाष शर्मा कहते हैं कि चुनाव परिणाम आज भले ही हमारे लिए प्रतिकूल हो लेकिन एक बात तय है कि पंजाब में विपक्ष के लिए स्पेस अब भी खाली है।

कमिश्नर और आइजी की मौजूदगी में हुआ दिवंगत बुआ-भतीजी का अंतिम संस्कार, पुलिस बल तैनात

उन्नाव । गुरुवार रात मृतक किशोरियों का अंतिम संस्कार न हो पाने के बाद शुक्रवार सुबह कमिश्नर व आइजी गांव पहुंचे और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करवा दी। इसके बाद सुबह नौ बजकर 45 मिनट दिवंगत बुआ और भतीजी का अंतिम संस्कार करा दिया गया। बता दें कि दोनों अधिकारी मृतक किशोरियों के स्वजन से अकेले में मिले और उनके राजी होने के बाद तैयारी शुरू करवाई थी ।

ये है पूरा मामला -जिले के एक गांव में बीते बुधवार एक ही परिवार की तीन किशोरियां गांव के बाहर खेत में अचेत अवस्था में मिली थीं। स्वजन उन्हें लेकर पहले नजदीक के एक निजी अस्पताल ले गए। जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया तो स्वजन उन्हें सरकारी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने दो को मृत घोषित कर दिया

जबकि, एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से डॉक्टर ने उसे कानपुर के निजी अस्पताल भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम होने के बाद शवों को गांव ले जाया गया और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की गई। विपक्षी दल के नेताओं व स्वजन के रात में अंतिम संस्कार का विरोध करने पर इसे सुबह के लिए टाल दिया गया।

शुक्रवार सुबह हुआ अंतिम संस्कार सुबह कमिश्नर रंजन कुमार व आइजी लक्ष्मी सिंह, एसपी आनंद कुलकर्णी लाव लश्कर के साथ गांव पहुंचे और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करवाई। इस बीच अधिकारियों ने दोनों के परिवार वालों से अकेले में बात की। इसके बाद एक शव को अंतिम संस्कार के लिए घर से निकले अधिकारी दूसरे शव को लेने गए। गांव में बड़ी तादात में फोर्स के बीच अंतत- दोनों किशोरियों के शवों को दफना दिया गया।

गांव के चारों ओर रहा खाकी का सख्त पहरा -किशोरियों के अंतिम संस्कार में कोई विरोध उत्पन्न न करने पाए इसके अंतर्गत अफसरों ने गांव के मुख्य मार्गों पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया। पुलिस ने पहला बैरियर असोहा पाठकपुर मार्ग के पहले मोड़ पर दूसरा पाठकपुर-बबुरहा मार्ग पर, तीसरा गांव से 50 मीटर की दूरी पर, चौथा दक्षिणी दिशा में पिकेट लगाई। पुलिस की फोर्स चप्पे-चप्पे पर तैनात रही। गांव में कमिश्नर रंजन कुमार, एडीजी एसएन साबत, डीएम रवींद्र कुमार, आइजी लक्ष्मी सिंह एसपी आनंद कुलकर्णी, एडीएम राकेश सिंह, एसडीएम राजेश चौरसिया के अलावा सत्ता पक्ष से पुरवा विधायक अनिल सिंह और मोहान विधायक ब्रजेश रावत भी मौजूद रहे।

फील्ड यूनिट टीम ने फिर किया घटनास्थल का निरीक्षण

घटना के तीसरे दिन शुक्रवार की सुबह किशोरियों के अंतिम संस्कार हो जाने के बाद फील्ड यूनिट की टीम फिर से घटनास्थल पर पहुंची और एक-एक जगह का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। इस दौरान डाग स्क्वायड की टीम घटनास्थल पर सर्च करती रही।

लुधियाना में लोक इंसाफ पार्टी ने डिंपल सिंह को बनाया वार्ड नंबर-31 का प्रधान

लुधियाना । लोक इंसाफ पार्टी महिला विंग पंजाब की प्रधान शशि मल्होत्रा ने पार्टी के प्रति सेवाओं को देखते हुए डिंपल सिंह को नगर निगम लुधियाना के वार्ड नंबर-31 का प्रधान नियुक्त किया है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सूबा प्रधान शशि मल्होत्रा ने कहा कि लोक इंसाफ पार्टी के महिला विंग को जिला, विधानसभा हलका, ब्लाक एवं वार्ड स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए नई नियुक्तियां की जा रही हैं। पार्टी की जन हितैषी एवं भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों को देखते हुए पंजाब में लोग अब पार्टी से जुड़ रहे हैं।

मल्होत्रा ने दावा किया कि पार्टी में आने वालों को उचित सम्मान दिया जाएगा। वर्ष 2022 के विधानसभा

चुनावों में लोक इंसाफ पार्टी प्रभावशाली तरीके से उभर कर सामने आएगी। विधानसभा चुनावों में पार्टी के महिला विंग की भूमिका अहम होगी। इस अवसर पर डिंपल सिंह ने कहा कि पार्टी की ओर से दी जिम्मेदारी को तनदेही से निभाएगी। इसके साथ ही पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर हलका प्रधान कमलजीत कौर, अमरजीत कौर, नरिंदर कौर, रजनी, चरणजीत कौर, रविंदर कौर, सोनम, अमरावती, रेखा, गीता, वंदना समेत कई सदस्य मौजूद रहे।

लुधियाना। राहों रोड की इंदिरा कालोनी के रहने वाले लोक राज पार्टी के नेता बलकार सिंह ने खुद व उनके बेटे पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस कमिश्नर को शिकायत देकर आरोपितों पर केस दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की। बलकार सिंह ने कहा कि उन पर हमला करने वाले व्यक्ति को राहों रोड और आसपास के इलाकों में दबंगई के लिए जाना जाता है। वो भविष्य में उन पर जान या माल का नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने थाना बस्ती जोधेवाल में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।

लालू को कोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद में पूरा परिवार, राबड़ी आवास के बाहर जुटे समर्थक कर रहे प्रार्थना

पटना । बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जेल से रिहाई के लिए आज उनके समर्थक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। लालू फिलहाल चारा घोटाले के एक मामले में सजा काट रहे हैं। इस मामले में जमानत के लिए लालू की याचिका पर आज झारखंड की रांची कोर्ट में सुनवाई होनी है। लालू प्रसाद को जमानत मिलने की उम्मीद पर उनके छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि शुक्रवार को सुनवाई होनी है। उम्मीद है कि इस बार राहत मिलेगी। इधर, लालू की रिहाई की उम्मीद लिये उनके समर्थकों की भीड़ पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर जुटने लगी है।

लालू ने अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर कोर्ट से जमानत मांगी है। उनकी ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मौजूदा मामले में वे अपनी आधी सजा पूरी कर चुके हैं। इसलिए उनकी बढ़ती उम्र और खराब सेहत को देखते हुए जमानत दी जाए। लालू के खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रांची की जेल से नई दिल्ली स्थित एम्स में ट्रांसफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गुरुवार को तेजस्वी ने बताया कि अभी उनकी तबीयत स्थिर है। किडनी में दिक्कत है। निमोनिया के चलते फिर से जांच की गई है। अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं।

लालू से जुड़े दो मामलों पर आज होनी है सुनवाई- कोर्ट में आज लालू की जमानत याचिका के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में भी सुनवाई होनी है। उनके खिलाफ जेल में रहते हुए फोन का इस्तेमाल कर बिहार की नीतीश सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप है।

बंगाल में 1500 से अधिक रैलियां आयोजित करने की तैयारी में भाजपा

कोलकाता । विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में भाजपा प्रचार की ऐसी आंधी लाने की योजना बना रही है, जिसमें मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का किला ध्वस्त हो जाए। बंगाल में भाजपा सौ-दो सौ नहीं बल्कि 1,500 से अधिक चुनावी रैलियों की योजना बना रही है। इन रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के अलावा पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता संबोधित करेंगे।

परिवर्तन यात्रा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विधानसभा स्तर पर बड़ी रैलियां की जाएंगी। 1,500 से अधिक जनसभाएं आयोजित की जाएंगी और प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता भाग लेंगे। बंगाल में पार्टी के कार्यक्रम की तैयारियों से जुड़े एक भाजपा नेता ने कहा कि राज्य के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने और उनके साथ सीधा संवाद स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच से छह रैलियां की जाएंगी और पार्टी के वरिष्ठ नेता इन्हें संबोधित करेंगे। एक अन्य भाजपा नेता ने बताया कि पार्टी के पास सरकार या संगठन में विभिन्न पदों पर आसीन नेता बंगाल में आयोजित होने वाली इन रैलियों को संबोधित करेंगे।

रैलियों की प्रारंभिक योजनाओं को साझा करते हुए, भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ संसदीय सीटों पर कलस्टर स्तर पर रैलियां करेंगे, जबकि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या कुछ विधानसभा सीटों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी शासित राज्य सरकारों के वरिष्ठ नेता विधानसभा स्तर पर रैली को संबोधित करेंगे। वे एक विशेष विधानसभा सीट पर जमीनी स्तर पर आवश्यकता के अनुसार कई रैलियां करेंगे।

बड़ी रैलियों के अलावा, पार्टी छोटे समूहों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए छोटी रैलियों को आयोजित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी कुछ सौ या हजार लोगों की छोटी रैलियां आयोजित करने की भी योजना बना रही है।

2019 में राज्य में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें जीती थीं। भगवा पार्टी ने अब बंगाल के चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता पिछले कुछ माह में प्रदेश भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

जेल से रिहा होकर 500 कारों के काफिले संग घर पहुंचा गैंगस्टर गजानन मार्ने

मुंबई । नई मुंबई की तलोजा जेल से सोमवार को रिहा हुए पुणे के एक गैंगस्टर का जुलूस देखकर तो उत्तर प्रदेश और बिहार के कथित माफिया सरगना भी पानी-पानी हो जाएं। ताज्जुब यह कि नई मुंबई से पुणे तक एक्सप्रेस वे पर तहलका मचाते हुए गए इस जुलूस की खबर उस दिन महाराष्ट्र पुलिस को भी नहीं लगी। प्राथमिकी दर्ज हुई अगले दिन, जब इंटरनेट पर इस जुलूस की फुटेज वायरल होने लगीं। तलोजा जेल से रिहाई हुई थी दो हत्याओं के आरोपित 46 वर्षीय गजानन मार्ने उर्फ गाजा पंढरीनाथ मार्ने उर्फ महाराज की। जेल से बाहर आए गजानन की अगवानी के लिए उसके समर्थकों की बड़ी भीड़ मौजूद थी। वह स्वयं एक कार में छत का शीशा हटाकर खड़ा हुआ लोगों का अभिवादन कर रहा था। उसके आगे-पीछे 500 कारों का काफिला चल रहा था। जगह-जगह पटाखे फोड़े जा रहे थे। ड्रोन के जरिए इस जुलूस की शूटिंग हो रही थी।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे के किसी भी टोल नाके पर काफिले की किसी कार द्वारा कोई टोल अदा किए बिना यह यह जुलूस निर्विघ्न पुणे पहुंच गया। राज्य की पुलिस को पता तब चला, जब इस जुलूस के वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगे। तब पुणे की हिंजेवाड़ी न तलेगांव पुलिस थानों में उसके खिलाफ अलग-अलग दो प्राथमिकी दर्ज की गईं। बताया जाता है कि गजानन पुणे में सक्रिय सात माफिया गुटों में से एक का सरगना है। वह दो हत्याओं के मामले में पिछले छह साल से जेल में बंद था। उस पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत भी मामला दर्ज था। पुणे के सत्र न्यायालय ने उसे व उसके 13 साथियों को इन मामलों से हाल ही में बरी किया है। पुणे के एसीपी-क्राइम ब्रांच सुरेंद्र देशमुख का कहना है कि पुणे के सभी आपराधिक गुटों पर हमारी नजर है। हमने अवैध जुलूस निकालने के मामले में गजानन पर भी मामला दर्ज कर लिया है।

दूसरी ओर, गजानन के वकील विजय थोम्बारे सफाई देते हुए कहते हैं कि गजानन को खुद नहीं मालूम था कि उसके स्वागत के लिए जेल के बाहर इतने लोग खड़े होंगे। जुलूस की ड्रोन से हुई शूटिंग के बारे में भी किसी को नहीं मालूम था। हमारे मुवक्किल के विरुद्ध इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करना उसे पुनः जेल भेजने की एक साजिश मात्र है। पुणे में सक्रिय कथित सात आपराधिक गिरोहों में से कुछ के रिश्ते यहां के राजनीतिक दलों से भी है। इनमें से ज्यादातर माफिया सरगना तेजी से विकसित हो रहे पुणे में भूखंडों पर कब्जे या भवन निर्माताओं से वसूली के दम पर मालामाल हो रहे हैं। इनमें आपस में टकराव की आशंका भी बनी रहती है। हाल ही में ऐसा ही एक सरगना पुणे महानगरपालिका में अपने समर्थकों के साथ बेखौफ टहलता देखा गया था। क्योंकि उसकी मां को शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा में कोई जिम्मेदारी मिली थी। इस सरगना पर भी कई मामले दर्ज हैं। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के दौरान खराब स्वास्थ्य के बहाने वह जमानत पाने में कामयाब रहा था। तब से वह बेखौफ घूमता दिखाई देता है।

कांग्रेस के डेटिंग डेस्टिनेशन के वादे पर गरमायी राजनीति, भाजपा ने बताया संस्कृति के विरुद्ध

अहमदाबाद । स्थानीय निकाय चुनाव के मतदान से ठीक पहले वडोदरा में कांग्रेस ने युवक-युवतियों से डेटिंग डेस्टिनेशन का वादा करके राजनीतिक माहौल को गरमा दिया, वही भाजपा ने इसे लव जिहाद से जोड़कर इसे संस्कृति के विरुद्ध बताया है। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वड़ोदरा, जामनगर तथा भावनगर महानगर पालिका के लिए आगामी रविवार को मतदान होना है।

कांग्रेस ने पुराने वादों को हेरफेर कर फिर परोसा- भाजपा में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में जहां पुराने वादों को ही हेरफेर करके फिर से परोस दिया है, वही वडोदरा शहर के लिए कांग्रेस की ओर से तैयार चुनावी घोषणा पत्र में युवक-युवतियों से डेटिंग डेस्टिनेशन का वादा करके कांग्रेस ने राजनीतिक घोषणाओं में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। दरअसल वडोदरा का महाराजा सयाजीराव गायकवाड विश्वविद्यालय देश तथा दुनिया के युवाओं के लिए शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है।

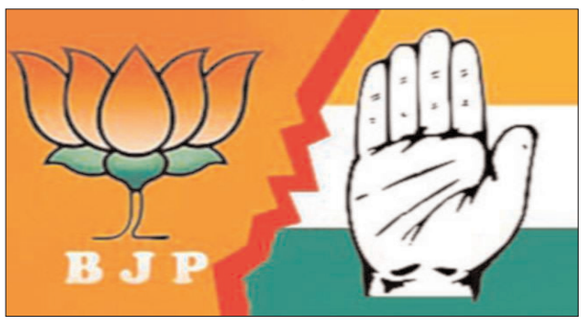

भाजपा ने किया कांग्रेस के वादे का विरोध- गुजरात के अलावा वडोदरा एक अलग संस्कार व संस्कृति के केंद्र के रूप में पहचान बना चुका है, ऐसे में वडोदरा कांग्रेस युवाओं की भावनाओं से जुड़ने के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में डेटिंग डेस्टिनेशन अर्थात कॉफी शॉप्स जैसे स्थल उपलब्ध कराने का भी वादा कर रही है। वड़ोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉ विजय शाह ने कांग्रेस की इस घोषणा को सीधे लव जिहाद से जोड़कर कांग्रेस के इस वादे का कड़ा विरोध किया है।

युवाओं की भावनाओं की कद्र

डॉक्टर शाह का कहना है कि वडोदरा गुजरात का संस्कार सिटी है तथा कांग्रेस संस्कार नगरी में डेटिंग के लिए युवाओं को कॉफी शॉप्स तथा अन्य स्थल उपलब्ध कराने की बात करके यहां की संस्कृति को खराब करने की मंशा रखती है। उधर कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव का कहना है कि गुजरात में एक परिवर्तन की लहर है तथा वडोदरा वासी कांग्रेस के साथ मिलकर इस बार शहर में जरूर बदलाव लाएंगे। उनका यह भी कहना है कि आज बड़ी संख्या में युवा मतदाता देश में हैं तथा युवाओं की भावनाओं की कद्र की जानी चाहिए। अगर कांग्रेस डेटिंग डेस्टिनेशन की बात करती है तो इसे गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए यह एक स्वतंत्र माहौल तैयार करने का एक प्रयास है ताकि युवक-युवती स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकें।

गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा नेता की दो पत्नियां आमने-सामने

अहमदाबाद । गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव का रंग जमा हुआ है, लेकिन पोरबंदर नगर पालिका की वार्ड तीन में भाजपा नेता की दो पत्नियों के आमने-सामने आ जाने से मुकाबला रोमांचक हो गया है। पोरबंदर नगर पालिका के वार्ड तीन में उषाबेन सीडा भाजपा की उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने शांताबेन सीडा को प्रत्याशी बनाया है। ये दोनों ही महिलाएं भाजपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशुभाई सीडा की पत्नी हैं। केशुभाई की पहली पत्नी उषाबेन जहां जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं, वहीं दूसरी पत्नी शांताबेन तहसील पंचायत की सदस्य रही हैं।

अब दोनों के एक ही वार्ड में दो अलग दलों से आमने-सामने आ जाने से मुकाबला रोचक बन गया है। हालांकि केशुभाई अपनी पहली पत्नी उषाबेन के साथ हैं तथा कहते हैं कि कांग्रेस को यहां कोई प्रत्याशी नहीं मिलता, इसलिए उनकी पत्नी को ही टिकट दे दिया। उन्होंने गत दिनों दूसरे मकान में रह रही शांताबेन के घर के बाहर जाकर धमकी दी तथा तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद शांताबेन ने उन के खिलाफ पुलिस केस कर दिया।

भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तथा अन्य दलों के प्रत्याशी गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में कई रोचक तरीके अपना रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जहां महंगाई तथा पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में कहीं बैलगाडी पर बैठकर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं तो कहीं स्कूटर को बैलगाड़ी पर सवार कर उस पर बैठकर प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष परेश धनाणी घरेलू गैस के दाम बढ़ोतरी का विरोध जताने को सिलेंडर पर बैठकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहीं साबरकांठा में कांग्रेस प्रत्याशी बैलगाडी पर बैठकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं।

भाजपा कार्यकर्ता नहीं बनें पुलिसकर्मी- परेश धनाणी

गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेश धनाणी ने राजकोट पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। धनाणी का आरोप है कि वह भाजपा के कार्यकर्ता बनकर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। धनाणी ने कहा कि भाजपा पुलिस वालों को अपना चपरासी समझती है, इसलिए पुलिस को यह समझना चाहिए कि उनका वेतन भाजपा कार्यालय से नहीं आता है।

किसानों को सहजता से मिलेंगी ऋण पुस्तिकाएं : एसडीएम

सिहोरा में पत्रकार संघ की पहल पर दिया आश्वासन

सिहोरा (एजेंसी)। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के बाद से तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारियों के पास ऋण पुस्तिका नहीं होने से किसान अपनी भूमि के क्रय विक्रय डायवर्सन नामांतरण किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत परेशान हैं। श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र दुबे के नेतृत्व में पत्रकारों ने नवागत एसडीएम शाहिद खान से मुलाकात कर किसानों को ऋण पुस्तिका नहीं होने से हो रही परेशानी से अवगत कराया।

एसडीएम को नगर की अन्य ज्वलन्त समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाते हुए पत्रकार प्रवीण कुरिया, अनिल अग्रवाल, अनिल जैन, अंकुर गुप्ता, करीम खान, गंगा पटेल , विजय तिवारी आदि ने समस्याआं की जानकारी दी। इसपर एसडीएम ने मौके पर जिलाध्यक्ष कार्यालय में संबंधित विभाग प्रमुख से मोबाइल फोन पर बात कर सिहोरा तहसील के लिए दो हजार ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराने को कहा तथा नगर स्थित चार राशन दुकानों में पात्र हितग्राहियों को कम राशन मिलने की समस्या पर एसडीएम ने दोनों समस्याओं पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके पहले संघ के सदस्यों ने नवागत एसडीएम को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया।

सूची से हटाएं वार्ड से विलुप्त हो चुके मतदाताओं के नाम

एनएसयूआई ने एसडीएम रांझी को शिकायत सौंपकर जताई आपत्ति

जबलपुर (एजेंसी)। केंट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सुभाष चंद्र बनर्जी वार्ड क्रमांक 65 सिविल लाइन की मतदाता सूची से वार्ड से विलुप्त हो चुके मतदाताओं के नाम हटाये जायें। उपरोक्त मांग को लेकर एनएसयूआई की ओर से गुरुवार को रांझी एसडीएम को शिकायतपत्र सौंपा गया। शिकायत के दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विजय रजक ने बताया कि संगठन की ओर से वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज 823 मतदाताओं के नामों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है।

रांझी एसडीएम दीप्ति अवस्थी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करते हुए एनएसयूआई की ओर से बताया गया कि 8 फरवरी को चुनाव आयोग द्वारा नई मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसको लेकर एनएसयूआई व कांग्रेस

के कार्यकर्ताओं ने जब क्षेत्र का भौतिक परीक्षण किया तो वार्ड के 16 बूथों में 823 ऐसे मतदाताओं के नाम पाए गए जिनमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी है या जो शादी होने के पश्चात बाहर जा चुके हैं, या जो नौकरी से स्थानांतरण होने के बाद या व्यक्तिगत कारणों से कई वर्षों पहले जबलपुर से बाहर जा चुके हैं। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विजय रजक ने बताया कि 823 ऐसे मतदाताओं की पहचान निर्वाचन आयोग द्वारा दावे आपत्ति की निर्धारित तिथि पर इन सभी 823 फर्जी मतदाताओं की सूची विलोपन फॉर्म भरकर वार्ड के प्राधिकृत कर्मचारी को सौंप दी गई है लेकिन इसके बावजूद अभी तक वार्ड में एक भी बीएलओ भौतिक परीक्षण करने नहीं आया। ज्ञापन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक चिंटू चौकसे, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लखन ठाकुर, कौशल यादव, शुभम रजक, शुभांशु कनौजिया ने केंट विधानसभा की निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से 823 मतदाताओं का भौतिक परीक्षण कर जल्द उनका नाम वार्ड की मतदाता सूची से हटाने की मांग की है ।

दरबार-ए-बुनियादी में बिखरे बसंत पंचमी के रंग

जबलपुर। (एजेंसी)। शहर की कौमी एकता के मर्कज दरबारे बुनियादी में बसंत पंचमी पूरे पारम्परिक अंदाज में मनाई गई। मोहम्मद खादिम बाबा जमाली के मुताबिक हजरत अमीर खुसरो की परम्परा का निर्वहन करते हुए बाबा साहब के निवास पुराना पुल गोहलपुर से गागर-चादर जुलूस निकाला गया। दरबारे बुनियादी के सज्जादानशीन हाजी बाबा मेराज अहमद जमाली की कायाद में निकले गागर-चार जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए शामिल हुए। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में गश्त करने के बाद जुलूस दरबारे बुनियादी पहुंचा जहां चादरपोशी के बाद सभी धर्म के लोगों ने मिलकर देश की शांति-खुशहाली की दुआएं कीं।

नागरिकों ने समाज को दिया प्रेरणादायक संदेश

अनुपयोगी सामग्री से पार्क को बनाया आकर्षक

जबलपुर। स्नेह नगर विकास समिति के तत्वावधान में नगर निगम के अंतर्गत चलाए जा रहे स्वच्छता मिशन प्रभारी सहायक आयुक्त एकता अग्रवाल के निर्देशन में रानी दुर्गावती पार्क में कबाड़ में फेंके गए अनुपयोगी सामग्री से गार्डन को व्यवस्थित किया गया। इस दौरान अनुपयोगी सामग्री में शामिल प्लास्टिक, बॉटल, पुराने टायर, ड्रम आदि को रंग रोगनकर आकर्षक बनाया गया। जिसमें गार्डन के चारों तरफ मौसमी फूलों के पौधों का रोपण किया गया। जिससे पार्क का सौंदर्यीकरण हो सका। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह पहला पार्क होगा, जो सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष विनोद दुबे, आरएस पाण्डेय, रूपकिशोर प्यासी, आरके जैन, रश्मि यादव, केके जैन, विजय पाटिल, नीता पाण्डेय, हर्षिता माला, सुनील जैन, एसपी मिश्रा आदि ने पार्क के सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

अशोक सिंघल के भाई अरविंद ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 11 करोड़ रुपये

उदयपुर। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि संकलन के बीच सबसे बड़ा दान उदयपुर के अरविंद सिंघल ने दिया है। विहिप के दिवंगत नेता अशोक सिंघल के छोटे भाई अरविंद सिंघल ने मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बड़े भाई के सपने को पूरा होते देख बेहद खुशी हो रही है। उदयपुर ही प्रदेश के अग्रज व्यवसायियों में शुमार उदयपुर के अरविंद सिंघल ने मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये की राशि दो चरणों में दी है। इससे पहले उन्होंने पांच करोड़ रुपये प्रदान किए थे और बुधवार को छह करोड़ का चेक मंदिर निर्माण के सहयोगार्थ प्रदान किए। अरविंद सिंघल वॉलकैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वॉलकैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड माइनिंग के क्षेत्र के साथ ही बिजली के मीटर और उपकरण बनाने का काम करती है, जो भारत समेत कई दूसरे देशों में भी सप्लाई किए जाते हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर के नींव पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें देश के चुनिंदा लोगों को ही नींव पूजा के मुख्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। नींव पूजा के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तथा अरविंद सिंघल के भतीजे सलिल सिंहल और उनकी पत्नी शामिल थी। अरविंद सिंघल ने अपनी तबीयत खराब होने तथा कोरोना महामारी के चलते भूमि पूजन कार्यक्रम में जाने की असमर्थता जताने के बाद पूजन कार्यक्रम में सलिल सिंघल दंपती शामिल हुए थे।

बड़ी राहत : पासपोर्ट आवेदकों को वेरीफिकेशन के समय नहीं ले जाने होंगे वास्तविक दस्तावेज

कोलकाता । विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने के नियम को और सरल करते हुए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। पासपोर्ट बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदकों को वेरीफिकेशन के समय सभी ऑरिजिनल दस्तावेजों (पहचान पत्र) के साथ पासपोर्ट कार्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अब यह अनिवार्य नहीं है।

पासपोर्ट विभाग ने नई प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत डिजिटल लॉकर के दस्तावेजों को ही विभाग स्वत- जांच कर लेगा। लेकिन इसके लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय डिजिटल लॉकर के प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करनी होगी।

कोलकाता में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व सिक्किम) बिभूति भूषण कुमार ने गुरुवार को अपने कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट विभाग ने 13 ऐसे दस्तावेजों की तालिका तैयार की है, जो डिजिटल लॉकर से जुड़े हुए हैं। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आर्म लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र, बिजली बिल व टेलीफोन बिल शामिल है।

अगर आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय फॉर्म में इन दस्तावेजों का डिजिटल लॉकर से सत्यापन की अनुमति देते हैं तो

कार्यालय में आवेदन के वेरिफिकेशन के समय उन्हें इसके ऑरिजिनल दस्तावेज लाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने सभी दस्तावेजों को डिजिटल लॉकर में शामिल नहीं किया है। ऐसे में जो दस्तावेज डिजिटल लॉकर में शामिल नहीं किया गया है, उसके ऑरिजिनल कॉपी को वेरिफिकेशन के समय ले जाना होगा।

एक फरवरी से शुरू की गई है नई प्रक्रिया- क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि एक फरवरी से यह नई प्रक्रिया शुरू की गई है और अब रोजाना पांच से सात फीसद आवेदन डिजिटल लॉकर की अनुमति के साथ जमा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को शुरू करने से आवेदकों को काफी लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अब ऑरिजिनल सर्टिफिकेट साथ नहीं ले जाने होंगे। साथ ही पासपोर्ट विभाग को भी आवेदकों के दस्तावेजों को अलग से डिजिटल के रूप में अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

फर्जी वेबसाइटों से रहें दूर

इस मौके पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कुमार ने पासपोर्ट बनवाने से संबंधित फर्जी वेबसाइटों से दूर रहने के बारे में भी लोगों को सावधान किया। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में पासपोर्ट विभाग के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट खोले गए हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि विभाग 36 पेजों की बुकलेट के साथ पासपोर्ट के लिए 1500 रुपये व 60 पेजों की बुकलेट वाले पासपोर्ट के लिए दो हजार रुपये शुल्क लेता है। अगर किसी भी वेबसाइट पर इससे अधिक रुपये की मांग की जाती है तो वह फर्जी है। उन्होंने देश में चल रहे ऐसे नौ फर्जी वेबसाइटों की तालिका जारी की, जिसके माध्यम से पासपोर्ट बनाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है।

डोंबिवली में बर्थ-डे पार्टी में कोविड नियमों का उल्लंघन, 500 लोगों पर केस दर्ज

ठाणे । महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में जन्मदिन समारोह के लिए एकत्रित होकर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल्याण डोम्बिवली नगर निगम (केडीएमसी) के अनुसार 17 और 18 फरवरी की रात डेसलपाड़ा में जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया गया था।

केडीएमसी के वार्ड अधिकारी अक्षय गुड्गे को शिकायत मिली थी कि लोग कोरोनोवायरस मानदंडों का पालन किए बिना स्थानीय निवासी का जन्मदिन मनाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। सभी लोग बिना मास्क के थे और शारिरिक दूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा था। सूचना मिलते ही नगर निगम अधिकारियों ने परिसर का दौरा किया और बाद में में मेजबान और उपस्थित लोगों सहित लगभग 500 लोगों के खिलाफ मैनपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 269 और 270 , 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने के लिए अवज्ञा) और भीड़ के खिलाफ आपदा प्रबंधन नियंत्रण नियमों की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए महाविकास अघाड़ी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन सहित नए कोरोनोवायरस दिशानिर्देशों की घोषणा की है।

महिला पंडित ने कराई दीया मिर्जा और वैभव की शादी! नहीं हुई कन्यादान और विदाई की रस्म

एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने 15 फरवरी को प्रेमी वैभव रेखा से शादी कर ली। इस जोड़े ने एक अंतरंग समारोह में शादी की, जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए।दीया के विवाह समारोह का संचालन महिला पुजारी शीला अट्टा ने किया। दीया ने समारोह में शादी की पूरी विधि करवाने के लिए शीला अत्ता को धन्यवाद देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और पीढ़ी की समानता के बारे में बात की। उन्होंने लिखा, 'हमारे विवाह समारोह के आयोजन के लिए शीला अट्टा का शुक्रिया। इतना गर्व है कि हम एक साथ #RiseUp #GenerationEquality कर सकते हैं।'

दीया मिर्जा और वैभव रेखा ने कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। शादी मुंबई में उनके परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई। अदिति राव हैदरी भी शादी में शामिल हुईं।

दीया और वैभव विवाह स्थल से बाहर आए और शादी समारोह के बाद फोटोग्राफरों के लिए पोज़ दिया। अभिनेत्री ने बनारसी साड़ी को अपनी दुल्हन लुक के रूप में पहना था। दीया मिर्जा ने पहले बिजनेसमैन साहिल संघा से शादी की थी। लेकिन उनकी शादी नहीं चली और 2019 में उनका तलाक हो गया।

आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की मुश्किलें खत्म

मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने भंसाली प्रोडक्शंस, अभिनेता आलिया भट्ट और मुंबई के लेखक हुसैन ज़ैदी के माफिया क्वीन्स के खिलाफ निरोधक आदेश की मांग करने वाले एक मुकदमे को खारिज कर दिया है, जिसकी पुस्तक पर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी आधारित है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म की मुख्य भूमिका में आलिया भट्ट हैं। मुकदमा बाबूजी शाह ने दायर किया था, जिन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र होने का दावा किया था। गंगूबाई काठियावाड़ी को एक ऐसी महिला थी जो अपने साथी के साथ गुजरात से मुंबई आई थी, लेकिन उनके साथी ने ही उन्हें वेश्यावृत्ति के बाजार में बेच दिया था। पिछली शताब्दी के मध्य में, काठियावाड़ी ने कई अंडरवर्ल्ड अपराधियों के साथ संबंध बनाए और दक्षिण मुंबई के कुछ हिस्सों पर पकड़ बनाई। वह एक बड़े वेश्यालय की मालकिन बनीं और कहा जाता है कि उन्होंने मुंबई के रेड लाइट एरिया, कामठीपुरा में महिलाओं और अनाथों के उत्थान के लिए काम किया। 2011 में प्रकाशित, मुंबई के माफिया क्वीन्स नामक पुस्तक में काठियावाड़ी पर एक अध्याय था, जो बाबूजी शाह के अनुसार, उन्हें बदनाम करने वाला था, उनका आरोप था कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया और उसकी मृतक मां की निजता और आत्मसम्मान के अधिकार का उल्लंघन किया। फिर उन्होंने पुस्तक के प्रकाशन और संचलन के खिलाफ निरोधक आदेश मांगा। शाह ने उपरोक्त उपन्यास पर आधारित किसी भी फिल्म के प्रोमो के निर्माण, निर्देशन या प्रसारण करने वाले लेखकों और फिल्म निर्माताओं के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा मांगी थी। अधिवक्ता नरेंद्र दुबे के माध्यम से दायर वाद में कहा गया है कि लेखक ने उपन्यास लिखने से पहले अनुमति या सहमति नहीं ली है और इसके अलावा उपन्यास पर आधारित एक फिल्म बना रहे है। बाबूजी शाह ने दावा किया कि काठियावाड़ी के बारे में उनसे या परिवार के किसी अन्य सदस्य से कोई जानकारी नहीं मिली है, जो स्वर्गीय काठियावाड़ी के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी हैं।

शनाया कपूर ने शकीरा के गाने पर किया जबरदस्त बैले डांस

बॉलीवुड के एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी ग्लैमरस फोटोज और वीडियो को शेयर करके अपने फैंस का मनोरंजन करती दिखाई देती हैं। हाल ही में शनाया अपने एक डांस वीडियो को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस वीडियो में शनाया, शकीरा के गाने पर धमाकेदार बेली डांस करती दिखाई दे रही हैं। इस डांस वीडियो में शनाया के साथ उनकी बेली डांस की टीचर भी उनका साथ देते हुए दिखाई दे रही हैं। शनाया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस बेली डांस वीडियो में खास बात ये है कि शनाया ने कुल 60 सेकेंड के लिए डांस के दौरान सांस तक नहीं ली थी। वीडियो में शनाया ने ब्लैक आउटफिट को कैरी किया हुआ है। वीडियो को शेयर करते हुए शनाया कपूर ने लिखा, 'मैंने अपने इस बेली डांस वीडियो में 60 सेकेंड तक सांस नहीं ली। संजना मुथरेजा के साथ ड्रम सोलो करना हमेशा ही सबसे बेस्ट समय रहा है। बता दें, शनाया कूपर के इंस्टाग्राम पर 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हाल ही में शनाया ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक किया है। फैंस कई बार संजय कपूर से शनाया के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर सवाल कर चुके है।

उन्नाव मामले पर भड़कीं स्वरा भास्कर

यूपी का उन्नाव जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में दो नाबालिग लड़कियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं, तीसरी लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। अब उन्नाव में हुई इस घटना को लेकर लगातार बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के रिएक्शन आ रहे हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने उन्नाव में हुई इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया है। स्वरा भास्कर ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। एक तरफ उन्होंने यूपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी ट्वीट में यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी कह डाली है। स्वरा ने ट्वीट किया, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बाद भी जब दोषियों को सजा नहीं मिलती है, तब उन्नाव जैसी घटनाएं होती हैं। ऐसा तो तभी होता है जब सरकार जनसेवा को छोड़ मंदिर और गाय पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। स्वरा भास्कर ने यूपी के मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े किए है। उन्होंने लिखा, और क्या होना बाक़ी है? उत्तर प्रदेश में और क्या होना है कि अजय बिष्ट की सरकार का इस्तीफ़ा मांगा जा सके.. और राष्ट्रपति शासन लागू हो? इस घटना पर और भी कई सेलेब्स रिएक्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सभी प्रदेश सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सभी यही अपील कर रहे हैं कि इस मामले में तेज कार्रवाई हो और सभी दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। बता दें, बता दें, बुधवार शाम को 13 और 16 वर्षीय लड़कियों के खेत में शव मिले थे, वहीं, 17 साल की लड़की बेहोशी की हालत में थी। उन्नाव में घटी इस घटना के बाद बबुरहा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नौ थानों की पुलिस फोर्स को गांव में तैनात किया गया है। इसके अलावा, 19 दारोगाओं, 17 मुख्य आरक्षी और 30 सिपाहियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है।

गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने कहा- मैं भाई-भतीजावाद की उत्पाद नहीं हूं

गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने कहा कि वह भाई-भतीजावाद का उत्पाद नहीं हैं, क्योंकि उनको कभी भी कोई फिल्म ऑफर करने के लिए कोई फोन नहीं किया। उन्होंने 2015 में फिल्म सेकंड हैंड हसबैंड से बॉलीवुड में शुरुआत की। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने कहा है कि उन्होंने कभी किसी से कोई पेशेवर मदद नहीं ली। उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर फिल्मों की पेशकश की गई है और उन्हें नेपो-किड के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है। टीना ने 2015 में पंजाबी सिंगर एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के साथ फिल्म सेकंड हैंड हसबैंड के साथ बॉलीवुड में शुरुआत की। फिल्म जिसमें गीता बसरा और धर्मेंद्र भी थे, ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में, टीना ने कहा कि उनके पिता गोविंदा ने कभी भी फिल्म ऑफ़र के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर वह भाई-भतीजावाद का उत्पाद होती, तो वह 30-40 फिल्में पहले ही साइन कर लेती। ये चीज पापा ने काभी नहीं कि और न ही मैंने उनसे कभी पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यो किया। मुझे इसकी जरुरत इस लिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पिता ने बिन मांगे मुझे मदद की है। वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

यात्रा प्रतिबंधों के कारण चौथे टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे करेन

अहमदाबाद, (एजेंसी)। ऑलराउंडर सैम करेन कोरोना महामारी को देखते हुए लगे यात्रा प्रतिबंधों के कारण भारतीय टीम के साथ अहमदाबाद में चार मार्च से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट के लिएउपलब्ध नहीं हो पाएंगे। करेन अब सीमित ओवरों के लिए ही भारत दौरे पर आयेंगे। इंग्लैंड टीम प्रबंधन ने कहा, करन 26 फरवरी को सीमित ओवर की टीम के अन्य सदस्यों के साथ ही भारत आने वाली चार्टर्ड फ्लाइट में आएंगे और इंग्लैंड टीम के साथ जुड़ेंगे। वहीं इससे पहले करेन को चार मार्च से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट के लिए अहमदाबाद में पहुंचना था। कोरोना महामारी के कारण उनकी यात्रा में आ रही बाधा को देखते हुए उन्हें बाद ही में भेजने का फैसला किया गया।

इंग्लैड के साथ सीमित ओवरों की सीरीज टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के साथ यहां 12 मार्च से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड की टीमें तीसरा और चौथा टेस्ट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद पहुंच गयी हैं। दोनो टीमें अभी टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। शेष दो टेस्ट मैचों के बाद दोनों टीमें इसके बाद टी20 और वनडे सीरीज खेलेंगी। मौजूदा कार्यक्रम के मुताबिक इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर अपना आखिरी मैच पुणे में खेलेगी लेकिन अब इस शेड्यूल में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।

केन्द्र ने कहा, एनएसएफ को मान्यता देने में राहत का अधिकार

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली उच्च न्यायालय को दिये अपने जवाब में केन्द्र सरकार ने कहा है कि उसके पास राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को जरूरत और बदलाव के हालातों में मान्यता प्रदान करने के संबंध में खेल संहिता के प्रावधानों में राहत देने का अधिकार है। खेल मंत्रालय द्वारा एक हलफनामे में यह बात कही गयी जिसमें एक फरवरी को महासंघ को मान्यता देने के संबंध में राहत देने के लिये खेल संहिता में शामिल किये गये खंड पर रोक लगाने की बात की गयी थी। वहीं इससे पहले आवेदन दायर करने वाले वकील राहुल मेहरा ने कहा कि मंत्रालय राहत देने के खंड को शामिल कर अदालत के आदेश को नकारने या निरस्त करने का प्रयास कर रहा है। इसमें महासंघ को मान्यता देने से पहले खेल संहिता का पालन करना जरूरी था।

आटिज्म से पीड़ित लड़की ने रचा इतिहास

नई दिल्ली, (संवाददाता)। 12 साल की लड़की जिया राय ने मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक से गेटवे आफ इंडिया के बीच की 36 किमी की दूसरी आठ घंटे और 40 मिनट में पूरी कर इतिहास बना दिया है। जिया ने आटिज्म से पीड़ित होने के बाद भी यह रिकार्ड बनाया है। आटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार जिससे व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार और संपर्क प्रभावित होता है। इस तैराकी कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र तैराकी संघ के निरीक्षण में किया गया था जो भारतीय तैराकी महासंघ से मान्यता प्राप्त संस्था है। एक बयान में कहा गया, 12 साल की जिया ने बांद्रा-वर्ली सी लिंक से गेटवे आफ इंडिया के बीच की 36 किमी की दूसरी आठ घंटे और 40 मिनट में पूरी करके इतिहास रचा। वह आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर (एएसडी) से पीड़ित है और तैराकी में अपनी इस उपलब्धि को उसने आटिज्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित किया है।

आईपीएल आयोजन स्थलों पर अभी तक नहीं हुआ है फैसला : लक्ष्मण

चेन्नई, (एजेंसी)। सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटॉर वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है कि आईपीएल के 14 वें सत्र का आयोजन कहां होगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है। पूर्व बल्लेबाज लक्ष्मण के अनुसार अब तक इस मामले में बीसीसीआई ने किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी है हालांकि यह तय है कि आयोनज देश में ही होगा। कोरोना महामारी के हालातों को देखते हुए बीसीसीआई विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेगा। इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि आईपीएल एक हाई-प्रोफाइल टूनार्मेंट है और इससे विभिन्न हितधारक जुड़े हैं इसलिए सभी का ध्यान रखते हुए ही कोई फैसला लेना होगा।

इससे पहले चेन्नई में गुरुवार को हुई नीलामी में सभी टीमों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान कुल 292 खिलाड़ियों की बोली लगाई गई थी। वहीं करोना के कारण गत वर्ष आईपीएल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के तीन शहरों-अबू धाबी, दुबई और शारजाह मे किया गया था। इस दौरान दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी थी हालांकि बीसीसीआई ने इसके बाद भी आईपीएल से 4000 करोड़ रुपये से भी अधिक की कमाई की थी।

अर्जुन तेंडुलकर ने मुंबई इंडियंस का आभार जताया

नई दिल्ली, (संवाददाता)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14 वें सत्र में खेलने का अवसर पाने से उभरते तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर बेहद उत्साहित हैं। अर्जुन महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। अर्जुन पहली बार आईपीएल नीलामी में शामिल हुए थे और उन्हें 20 लाख रुपये के आधारमूल्य पर ही मुम्बई इंडियंस ने खरीदा है। नीलामी से पहले ही अर्जुन को जगह मिलना तय माना जा रहा था। अर्जुन का सफर आसान नहीं रहा है।वह भारतीय टीम के लिए नेट्स में गेंदबाजी करते रहे हैं। वह गत वर्ष मुंबई इंडियंस के साथ यूएई भी गए थे। अर्जुन ने एक वीडियो के जरिए मुंबई इंडियंस की टीम का आभार व्यक्त किया है। मुंबई इंडियंस के ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में अर्जुन ने कहा, बचपन से ही मैं मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मैं इसके बाद कोच, टीम मालिकों और सपॉर्ट स्टाफ का मुझमें भरोसा करने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ने साथ ही कहा, मैं मुंबई पल्टन की टीम का हिस्सा बनने से बेहद खुश हूं हूं और ब्लू गोल्ड जर्सी पहनने का इंतजार कर रहा हूं।

अमेरिका जाना चाहते हैं श्रीलंकाई क्रिकेटर

कोलंबो, (एजेंसी)। श्रीलंकाई क्रिकेट को झटका लग सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कई क्रिकेटर खेल को लेकर बने हालातों से खुश नहीं हैं और देश छोड़ने का विचार कर रहे हैं। इनमें से कुछ क्रिकेटर तो राष्ट्रीय टीम तक का हिस्सा रहे हैं। जबकि कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। अपनी ही धरती पर इंग्लैंड के हाथों मिली हार के बाद अब श्रीलंका के कई क्रिकेटरों के देश छोड़ने की आशंका बढ़ गई है। इससे श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) भी परेशान है। ये खिलाड़ी टीम में अवसर नहीं मिलने के साथ ही पर्याप्त वेतन नहीं मिलने के कारण भी देश छोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार से नाराज क्रिकेटर अमेरिका में बसने पर विचार कर रहे हैं, जहां वे अमेरिकी क्रिकेट के लिए खेल सकते हैं। इन खिलाड़ियों में उपुल थरंगा जैसे कम से कम 15 खिलाड़ियों के नाम हैं, जो अगले महीने तक अमेरिका का रुख करने की तैयारी में हैं।

कोरोना वैक्सीन लेने वाली पहली टीम बनी बांग्लादेश

नई दिल्ली (ईएमएस)। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ ही सहयोगी स्टाफ को भी कोरोना का टीका लग गया है। इस प्रकार कोरोना वैक्सीनेशन वाली वह पहली टीम बन गयी है। बांग्लादेश की टीम को अगले सप्ताह होने वाले न्यूजीलैंड दौरे से पहले यह टीका लगाया गया है। तमीम इकबाल सहित कई खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को कोरोना वैक्सीन दी गई। सबसे पहले सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार को टीका लगाया गया। इसके बाद तमीम इकबाल, मेहदी हसन, मोहम्मद नईम और तस्कीन अहमद ने टीका लगवाया।

इसके बाद कोच सहित सपोर्ट स्टाफ को टीका लगाया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के डायरेक्टर जलाल यूनुस ने भी इस दौरान टीका लगवाया। टीका लगाने के बाद तमीम ने कहा कि टीका सभी के लिए जरूरी है। इससे डर को दूर किया जा सकेगा। इस महीने बांग्लादेश सरकार ने टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है।

बांग्लादेश टीम को अपने न्यूजीलैंड दौरे पर तीन वनडे और तीन टी20 मुकाबले खेलने हैं। वनडे के मुकाबले 20, 23 और 26 मार्च को खेले जाएंगे। वहीं टी20 के मैच 28 मार्च, 30 मार्च और 1 अप्रैल को खेले जाएंगे। टीम 24 फरवरी को न्यूजीलैंड दौरे के लिए रवाना होगी। पितृत्व अवकार पर रहने के कारण अनुनभवी खिलाड़ी शाकिब अल हसन इस दौरे पर नहीं जाएंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो बांग्लादेश टीम का न्यूजीलैंड में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और उसे अबतक एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिली है।

विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और अन्य खिलाड़ी घरेलू मैच में भाग लेते हुए।

लॉस एंजिल्स में डस्टिन जोनसन जेनिसिस गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेते हुए।

इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में खेल सकते हैं पुजारा

नई दिल्ली, (संवाददाता)। टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में खेलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए काउंटी टीम वार्विकशायर से पुजारा की बात चल रही है। इसके पहले भी वे 2018 में काउंटी में जोनाथन ट्राट और इयान बेल के साथ खेल चुके हैं। पुजारा 2018-19 और 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों टीम की ओर से सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज थे। अभी उनकी रैंकिंग सात है। अगर पुजारा को काउंटी में अनुबंध मिलता है तो वे टेस्ट सीरीज के पहले कम से कम छह मैच खेल सकेंगे। पुजारा इसके पहले डर्बिशायर, नॉटिंघमशायर और यार्कशायर से खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 30 की औसत से 988 रन बनाए हैं। उनका औसत इंग्लैंड के टेस्ट रिकॉर्ड से खराब है। साल 2018 में दौरे के दौरान पुजारा ने 40 की औत से रन बनाए थे। इसमें एक शतक भी शामिल था। टीम इंडिया का इंग्लैंड में टेस्ट में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। टीम ने 62 में से सिर्फ 7 मुकाबले जीत हैं। 34 में हार मिली है जबकि 21 मैच ड्रॉ रहे। मौजूदा टेस्ट खिलाड़ियों की बात की जाए तो कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कोहली ने 10 मैच में 36 की औसत से 727 रन बनाए हैं इसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। वहीं पुजारा ने 9 मैच में 29 की औसत से 500 रन बनाए हैं।

घाना के मुक्केबाज से भिड़ेंगे लालरिनसांगा

नई दिल्ली (ईएमएस। भारत के पेशेवर मुक्केबाज लालरिनसांगा तलाउ को युवा विश्व सुपर फीदरवेट खिताब के लिये छह मार्च को घाना के एरिक क्वारम से मुकाबला होगा। आईजोल में होने वाले इस मुकाबले में कोविड-19 महामारी को देखते हुए दर्शकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पेशेवर सर्किट में 21 वर्षीय लालरिनसांगा ने चार मुकाबले लड़े हैं और वह अब तक वह सभी मुकाबले जीते हैं। इस भारतीय मुक्केबाज में अपना अंतिम मुकाबला 30 जनवरी को मुंबई में लड़ा था। अभी 57 किग्रा में उनकी विश्व रैंकिंग 276 है।

वहीं घाना के क्वारम को पांच मुकाबलों का अनुभव है जिसमें से चार में उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने आखिरी मुकाबला दिसंबर 2019 में लड़ा था। लागोस में हुए इस मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा था।

हाशिमोतो बनी टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति की नई अध्यक्ष

टोक्यो, (एजेंसी)। सीको हाशिमोतो आगामी टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति की नई अध्यक्ष बनी हैं। हाशिमोतो ने चार बार शीतकालीन और तीन बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के प्रधान कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद 56 वर्षीय हाशिमोतो को आयोजन समिति का अध्यक्ष चुना गया। वह पूर्व अध्यक्ष मोरी के इस्तीफे के बाद यह पद संभाल रही हैं। इससे पहले मोरी ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी के कारण हुए विरोध के बाद पद छोड़ दिया था। हाशिमोतो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की कैबिनेट में ओलंपिक मंत्री पद पर है। उनके पास लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा विभाग भी है। उन्होंने तीन

ग्रीष्मकालीन ओलंपिक (1988, 1992 और 1996) तथा चार शीतकालीन ओलंपिक (1984, 1988, 1992 और 1994) में हिस्सा लिया था। उन्होंने 1992 में स्पीडस्केटिंग में 1500 मीटर में कांस्य पदक जीता था। यह ओलंपिक में उनका एकमात्र पदक है। हाशिमोतो का ओलंपिक के साथ विशेष रिश्ता है। उनका जन्म तोक्यो ओलंपिक 1964 के उद्घाटन समारोह से पांच दिन पहले उत्तरी जापान के होकाइदो में हुआ था। उनका नाम सीको सीका से लिया गया है जिसका अर्थ ओलंपिक मशाल होता है।

अंतिम दो टेस्ट मैचों के लिए बदले नहीं जाएंगे मैच अधिकारी : आईसीसी

दुबई, (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने कहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले अंतिम दो टेस्ट मैचों के लिए मैच अधिकारी बदले नहीं जायेंगे। आईसीसी के अनुसार जवागल श्रीनाथ पूरी सीरीज में मैच रेफरी रहेंगे। वहीं अनिल चौधरी आईसीसी एलीट पैनल के अंपायर नितिन मेनन के साथ तीसरे डे-नाईट टेस्ट में शामिल होंगे जबकि वीरेंद्र शर्मा चौथे टेस्ट में मेनन के साथ मैदानी अंपायर की भूमिका निभाएंगे। आईसीसी ने इससे पहले कहा था कि वह पहले दो टेस्ट मैचों में चौधरी और शर्मा के प्रदर्शन का आंकलन करना चाहता था जिसके कारण ही मैच अधिकारियों की घोषणा में विलंब हुआ। चौधरी ने पहले टेस्ट में मैदान पर अच्छा प्रदर्शन किया पर उन्होंने दूसरे टेस्ट में तीसरे अंपायर की भूमिका के दौरान एक गलती कर दी थी जिसके कारण उन्हें हटाये जाने की बातें कही जा रहीं थीं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 24 फरवरी से गुलाबी गेंद से खेला जाएगा जबकि दोनों टीमों के बीच चौथा और अंतिम टेस्ट चार मार्च से होगा। यह दोनो ही मैच अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेले जाएंगे।

अगले दो टेस्ट के लिए मैच अधिकारी इस प्रकार हैं :

तीसरा टेस्ट : नितिन मेनन, अनिल चौधरी (मैदानी अंपायर), सी शमशुद्दीन (तीसरे अंपायर), केएन आनंथापदमानभान (चौथे अंपायर) और जवागल श्रीनाथ (मैच रेफरी)

चौथा टेस्ट : नितिन मेनन, वीरेंद्र शर्मा (मैदानी अंपायर), अनिल चौधरी (तीसरे अंपायर), सी शमशुद्दीन (चौथे अंपायर) और मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ।

ओलंपिक मशाल रिले हो सकती है रद्द

टोक्यो, (एजेंसी)। आगामी टोक्यो ओलंपिक की मशाल रिले रद्द हो सकती है। पश्चिमी जापान के एक प्रांत के गवर्नर ने टोक्यो ओलंपिक से पहले अपने क्षेत्र में होने वाली ओलंपिक मशाल रिले को रद्द करने के संकेत दिये हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार शिमेन प्रांत के गवर्नर तात्सुया मारुयामा मशाल रिले के दौरान कोविड-19 को रोकने के उपायों से नाराज बनाये जा रहे हैं। यह मशाल रिले मई में इस प्रांत से होकर गुजरेगी। गवर्नर ने कहा, हम केंद्रीय और टोक्यो मेट्रापोलिटन सरकारों के कोरोना वायरस को रोकने के उपायों से खुश नहीं हैं। मशाल रिले 25 मार्च को उत्तरपूर्वी जापान में शुरू होगी और उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरकर 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में पहुंचेगी। इस रिले में 10,000 धावकों के भाग लेने की संभावनाएं हैं।

नार्थईस्ट युनाइटिड और चेन्नईयिन का मुकाबला बराबरी पर रहा

बेम्बोलिम, (एजेंसी)। लुइस मचाडो के पेनल्टी पर किये गोल से नॉर्थईस्ट युनाइटेड एफसी और चेन्नईयिन एफसी के बीच इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। मचाडो के गोल से यह मैच 3-3 से बराबरी पर समाप्त हुआ। वहीं प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई चेन्नईयिन का यह 19 मैचों में 10वां ड्रॉ है। इस प्रकार उसके खाते में 19 अंक हो गये हैं। वहीं, नॉर्थईस्ट को 18 मैचों में नौवीं बार ड्रॉ खेलना पड़ा है। यह टीम 27 अंकों के साथ पांचवें नंबर पर है। चेन्नईयिन की ओर से लालियानजुआला चांगते ने आठवें और 51वें मिनट में दो गोल दागये। उसके लिये तीसरा गोल मैनुएल लेंजारोते ब्रुनो ने 50वें मिनट में पेनल्टी से किया। वहीं नॉर्थईस्ट युनाइटेड एफसी की ओर से इमरान खान ने 14वें और देशोर्न ब्राउन ने 43वें मिनट में गोल दागे।

ओरलैंडो में कनाडा की डिफेंडर वेनिसी और अन्य खिलाड़ी महिला फुटबॉल मैच में भाग लेती हुईं।